● वर्ष-4
● अंक-167
रायपुर, शुक्रवार
21 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» मलेशिया है बहुत ....

रेखा गुप्ता बनी मुख्यमंत्री

उपराज्यपाल ने रामलीला मैदान में दिलाई शपथ

नईदिल्ली। भाजपा की रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रामलीला मैदान में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिलाई।इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद रहे।उनके बाद प्रवेश साहिब सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन अलग-अलग मंच तैयार किए गए। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे।दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद थे।

बता दें कि बुधवार शाम विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया था। सीएम चुने जाने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जो दिल्ली की जनता के लिए विजन दिया है, उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी का तहे दिल से आभार जताना चाहती हूं कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि यह देश की हर मां-बेटी का सम्मान है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने %आप% की बंदना कुमारी को 29,595 मतों के अंतर से हराया था। गत 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भाजपा को 26 साल बाद ऐतिहासिक जीत मिली थी। उसने 70 में से 48 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई।

6 मंत्रियों ने भी ली शपथ

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलवाई इसके बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और अंत में रविंदर इंद्राज सिंह ने शपथ ली। शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान खचाखच भरा था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन अलग-अलग मंच तैयार किए गए। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में अपने पद की शपथ ग्रहण की। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 27 साल बाद पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापस आई है।

केजरीवाल को एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित अपने आवास के बाहर गुरुवार को पत्रकारों से कहा, पिछले 12 वर्षों से आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली पर शासन किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर हैं। उन्हें जनता के एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए एक नई प्रेरणा और एक नया अध्याय है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उनके साथ 6 मंत्री- प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह भी शपथ लेंगे।छह मंत्रियों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज दोपहर 12.35 बजे नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे।रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रामलीला मैदान में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान तैनात हैं।

जब प्रधानमंत्री मोदी ने थामा विष्णुदेव साय का हाथ- मंच पर दिखी खास आत्मीयता

नई दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली, लेकिन इस समारोह में एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया। मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो उन्होंने एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब बारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आई, तो माहौल अलग ही नजर आया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही आत्मीय अंदाज में विष्णुदेव साय का हाथ थाम लिया—और बस फिर क्या था! कुछ क्षणों के लिए मंच पर यह दृश्य खास बन गया। पीएम मोदी ने न सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि लंबे समय तक विष्णुदेव साय का हाथ थामे रहे, उनके हालचाल पूछते रहे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा की।

इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने उनसे भी बातचीत की, लेकिन खास बात यह रही कि उनके शब्दों के साथ-साथ विष्णुदेव साय का हाथ भी मजबूती से थामे रहे। दोनों नेताओं के बीच यह आत्मीय संवाद काफ़ी देर तक चला ।

रायपुर। । राजिम कुंभ कल्प मेला के दौरान तीर्थ क्षेत्र राजिम में उस वक्त दृष्य रोमांचित हो गया, जब नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली। नागा संत शरीर पर भस्म लगा कर अपनी जटाओं को लहराते हुए बैंडबाजा, डमरू, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर करतब दिखाते हुए शस्त्र प्रदर्शन किया।

योगी सरकार ने पेश किया 8.08 लाख करोड़ बजट

लखनऊ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।

योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें %आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी% की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रमुख समाचार

भारत दे सकता है तालिबानी राजदूत को दिल्ली आने की इजाजत

काबुल। भारत जल्द ही अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के राजदूत स्तर के प्रतिनिधि को नई दिल्ली आने की इजाजत दे सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर तालिबानी अधिकारी को राजनयिक के रूप में मान्यता नहीं देगा। तालिबान सरकार दिल्ली में अफगान दूतावास की देखरेख के लिए फिलहाल दो नामों पर विचार कर रही है। इनमें से एक नाम फाइनल करते हुए जल्दी ही उनको भारत भेजा जाएगा। तालिबान के प्रतिनिधि को दूतावास, आधिकारिक कार्यक्रम और राजनयिक वाहनों पर अपना झंडा लगाने की अनुमति नहीं होगी लेकिन तालिबान का यह नुमाइंदा भारत में अफगानिस्तान का शीर्ष प्रतिनिधि होगा।रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि दोहा में अफगान दूतावास में तैनात नजीब शाहीन नई दिल्ली में शीर्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। शाहीन एक दशक से तालिबान के साथ काम कर रहे हैं और कतर में तालिबान शासन के राजदूत के बेटे हैं। एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि शौकत अहमदजई भी इस रेस में हैं, जो तालिबान के विदेश मंत्रालय शीर्ष पद में काम करते हैं। दोनों नामों पर विचार चल रहा है।

राहुल गांधी के साथ सार्थक बातचीत हुईः थरूर

नईदिल्ली। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को नयी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में उनके आलेख के आधार पर एक मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है।

गांधी के साथ बैठक के बाद नयी दिल्ली से लौटने पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आधे घंटे की बातचीत के दौरान वह कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात कर पाए। बार-बार पूछे जाने पर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि वह बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के बारे में और जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों या केरल में नेताओं की भूमिका के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अपने आलेख को लेकर केरल में कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार आलोचना के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा कि वह विवाद का कारण नहीं समझ पा रहे हैं।उन्होंने कहा, राज्य के किसी भी नेता के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो उन्हें तय करने दें कि उसका समाधान हुआ है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर रोक लगाकर ''बहुत परेशान करने वाला'' आदेश करार दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका शामिल हैं। पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम उजागर करने से रोक दिया है। पीठ ने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाकर लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल ने खुद को हाई कोर्ट के मौजूदा जजों की जांच करने का अधिकारी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बेहद परेशान करने वाला करार देकर केंद्र और लोकपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लोकपाल ने 27 जनवरी को आदेश जारी कर हाई कोर्ट के एक मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दो शिकायतों पर कार्रवाई की थी।

मोदी के रहते मुमकिन नहीं है 370 की वापसीः सीएम अब्दुल्ला

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भले ही केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बताए जाते हैं लेकिन मौका आने पर उमर अपनी बात कहने से नहीं चूकते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं तो उनकी सरकार केंद्र के साथ अपने संबंधों को लेकर पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि पीएम मोदी के रहते जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की वापसी नहीं हो सकती है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला से जब यह पूछा गया कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बहाल होने की कोई संभावना है? उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है।उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति अपनी दृष्टिकोण को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले कुछ महीनों में केंद्र के साथ एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण था।

महाकुंभ मुक्ति मेला है, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ताः राज्यपाल

नईदिल्ली. कुम्भ ईश्वर से मिलन है। जो साधारण व्यक्ति स्वेच्छा से वहाँ आये थे। उनमें से लाखों-करोड़ों लोग अपने आप आए क्योंकि वे वहां रहना चाहते थे। मुझे लगता है कि यह एक इंद्रधनुषी पुल है जो धरती को आकाश से, मनुष्य को भगवान से, आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ता है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को कुंभ मेले को मुक्ति मेला (स्वतंत्रता मेला) बताया, जिसने मनुष्य को भगवान से जोड़ने वाला एक इंद्रधनुष पुल बनाया। उनका बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के कुछ दिनों बाद आया है कि महाकुंभ भगदड़ की घटनाओं के कारण मृत्यु कुंभ में बदल गया है, उन्होंने दावा किया था कि मेगा धार्मिक सभा में वास्तविक टोल को अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया था। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मुख्यमंत्री को अपनी राजनीतिक स्थिति के आधार पर किसी भी स्थिति का अपना विश्लेषण देने का अधिकार है। बोस ने यहां राजभवन में पत्रकारों से कहा कि मैं लोकतंत्र की सुंदरता के रूप में इसका स्वागत करता हूं।

चीन- रूस और भारतीय अवैध प्रवासियों के साथ अमेरिका का भेदभाव

सनत जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अवैध प्रवासियों की तीन खेप को सेना के विमान में भारत भेज दिया है। 300 से अधिक भारतीय अवैध प्रवासी भारत वापस लौट चुके हैं। खास यह है कि इन सभी को हथकड़ियों और वेड़ियो में जकड़ कर भेजा गया है। सेना के लड़ाकू विमान जिसमें बैठने के लिए सीट नहीं होती हैं, खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक इमरजेंसी टॉयलेट भरा होता है। उसमें अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका में चीन और रूस के तीन लाख से अधिक अवैध प्रवासी रह रहे हैं। चीन और रूस के अवैध प्रवासियों को भेजने की कोई प्रक्रिया अमेरिका द्वारा शुरू नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा पूरी तरह से अब जग जाहिर हो गया है। वह भारत और भारत के अवैध प्रवासियों के साथ अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस द्वारा अवैध प्रवासियों को जिस तरह से भारत भेजा गया, उसका वीडियो बनाया गया। वेड़ियो और हथकड़ियों में जकड़े महिला, पुरुषों और बच्चों को भेजने का यह वीडियो 5 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में देख चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके सलाहकार एलन मस्क वीडियो में अटहास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका जानबूझकर भारत के अवैध प्रवासियों के साथ गुलाम और अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। भारत की जो विश्व गुरु वाली छवि सारी दुनिया के देशों में बनी हुई थी उस छवि को सुनयोजित रूप से नष्ट किया जा रहा है। अमेरिकी गृह मंत्रालय के अनुसार चीन के 260000 रूस के 30000 से ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों के भी लाखों अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन भारत के अवैध प्रवासियों को अमेरिका से जिस तरह से वापस भेजा जा रहा है उससे यह बात स्पष्ट हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले

चीन और अन्य देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन एक महीना होने को आ गया चीन और अन्य देशों के साथ उन्होंने जो धमकी दी गई थी उसके अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की। सारी गाज भारत के ऊपर गिरती हुई दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों तंज कसा है, भारत के पास खूब पैसा है। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करने वाला देश है। यह कहते हुए उन्होंने जो भारत को सहायता दी जा रही है उसे भी बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका की धमकी के आगे भारत ने बहुत सारी चीजों में आयात शुल्क घटा दिया है। अमेरिका के दौर में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस समय अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे समझौते किए हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह हैं। यह माना जा रहा था कि अवैध प्रवासियों को लेकर वह सकारात्मक रुख अपनाएंगे। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी को लेकर अमेरिका का सकारात्मक रुख होगा, लेकिन 18 फरवरी को अमेरिका न्याय विभाग ने जो पत्र भारत सरकार को भेजा है उसके बाद यह आशा भी खत्म हो गई। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क जानबूझकर भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। भारत सरकार अमेरिका से इतना क्यों डर रही है, इसको लेकर अब दुनियाभर में चर्चा होने लगी है। छोटे से छोटे देशों ने अमेरिका के ऊपर जवाबी हमले किए, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौन साधना पड़ा। भारत सरकार की चुप्पी सभी को आश्चर्य चकित कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साक्षी न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यह बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मिले थे तब उन्होंने प्रतिस्पर्धी टैरिफ लगाने की बात उन्हें बता दी थी। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर भी उनसे चर्चा हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है, भारत सरकार कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। बहरहाल दुनिया के देशों में भारत की जो छवि बनी हुई थी वह बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। अब तो लोग यह भी कहने लगे हैं अमेरिका की सरकार भारत के साथ गुलामो सरीका व्यवहार कर रही है। पिछले 1 महीने में अमेरिका की सरकार ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वह किसी को रास नहीं आ रहा है। लोग अब 1971 के युद्ध से तुलना करने लगे हैं।

18 करोड़ का स्ट्रीट लाइट घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र, अगली सुनवाई 18 मार्च को

बिलासपुर। बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का स्ट्रीट लाइट घोटाला किया गया है. मामले में हाईकोर्ट के स्व-संज्ञान के बाद चल रही जनहित याचिका में सुनवाई जारी है. बुधवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो चुकी है जो अपना काम कर रही है. इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शासन से शपथपत्र में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी है.

बस्तर और सुकमा जिले के 190 गांवों में लगा दी गई 18 करोड़ रुपये की 3500 से ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट नियमों को दरकिनार कर लगा दी गई. इस खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. पूर्व में हुई सुनवाई में बताया गया कि पूरी निविदा प्रक्रिया क्रेडा के माध्यम से होनी चाहिए थी, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई है. राज्य के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की है. अतिरिक्त महाधिवक्ता राज कुमार गुप्ता ने बताया था कि जब उपरोक्त तथ्य अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो दिनांक 09.04.2024 को आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा जांच का आदेश दिया गया. जांच भी पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है. बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो गई है. जल्द ही वास्तविक रिपोर्ट सामने आ जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप शासन की ओर से शपथपत्र में विस्तृत जानकारी पेश करें.

बेलपोच्चा के पुलिया के पास आईईडी लगाने वाला नक्सली विस्फोटक के साथ गिरफ्तार

सुकमा। नक्सली उपस्थित की आसूचना थाना कोंटा से जिला बल का बल एवं कैम्प मुरलीगुड़ा से जी/228 वाहिनी सीआरपीएफ बल की संयुक्त पार्टी ग्राम बेलपोच्चा की ओर सर्चिंग अभीयान पर रवाना हुए थे।अभियान के दौरान के ग्राम बेलपोच्चा के पास 1 संदिग्ध युवक को पकड़ा गया पुछताछ करने पर अपना नाम मुचाकी देवा पिता मुचाकी हुंगा उम्र 18 वर्ष साकिन बेलपोच्चा थाना कोंटा जिला सुकमा का होना तथा नक्सल संगठन में मेहता आरपीसी में मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना स्वीकार किया। पकड़े गये नक्सली आरोपी के निशानदेही पर पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छूपाकर रखे 4 नग जिलेटिन राड, 4 नग इलेक्ट्रीक डेटोनेटर, करीबन 1.5 मीटर कोर्डेक्स वायर एवं नक्सल पाम्पलेट को बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सली एवं बरामद सामग्री को थाना लाकर नक्सल रिकार्ड की जांच करने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना कोंटा मे अपराध क्रमांक 03/2025 धारा 190 बी.एन.एस., 4 (क) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1967 की धारा 13, 23, 38, 39 के तहत पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है।

107 साल बाद बस्तर राजमहल से निकली बारात हाथी पर सवार दिखे राजा कमलचंद भंजदेव

जगदलपुर। बस्तर राजघराने की शाही शादी का जश्न शुरू हो चुका है. हल्दी रस्म के बाद बस्तर गद्दी के राजा कमलचंद भंजदेव की शाही बारात शहर की सड़कों पर ऐतिहासिक भव्यता के साथ निकली. इस शाही बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल थे, जिन पर राजपरिवार का शाही चिन्ह सुसज्जित था.

कमलचंद भंजदेव हाथी पर सवार होकर राजमहल से निकले और मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने के बाद बारात रवाना हुई. बारात में माझी चालकी और पुरानी बस्तर रियासत के पारंपरिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. बारात जगदलपुर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए वापस राजमहल पहुंची.

विशेष विमान से मध्य प्रदेश जाएगी बारात-कमलचंद भंजदेव अपनी बारात लेकर चार्टर्ड फ्लाइट से मध्य प्रदेश के नागौद राजमहल पहुंचेंगे, जहां विवाह संपन्न होगा. शादी के बाद विशेष विमान से ही बारात वापस जगदलपुर लौटेगी.

107 साल बाद निकली शाही बारात- इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी सड़कों पर उमड़ पड़े. आखिरी बार 107 साल पहले पूर्व महाराजा रुद्र प्रताप देव की बारात राजमहल से निकली थी. इतने वर्षों बाद कमलचंद भंजदेव ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया, जिससे जगदलपुर में खास उत्साह का माहौल देखने को मिला.

आदि महोत्सव में बस्तरिया व्यंजन के स्टॉल से 50 लीटर महुआ की शराब व 25 किलो चापड़ा चटनी की हुई खपत

बीजापुर। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में बीजापुर जिले के मुरकीनार गांव के नक्सल पीड़ित युवक राजेश यालम ने भी स्टॉल लगाया है, यह बस्तरिया व्यंजन का एक मात्र स्टॉल है। राजेश यालम ने बताया कि इस स्टाल में दिल्ली के लोगों को बस्तर का महुआ की शराब और चापड़ा चटनी (लाल चीटियों की चटनी) इतना पंसंद आया कि सिर्फ 2 दिनों में 50 लीटर महुआ की देशी शराब और 25 किलो चापड़ा चटनी चट कर गए। उन्होने बताया कि दिल्ली के लोगों ने कहना है कि बस्तरिया फूड लजीज है। राजेश यालम ने बस्तर की महुआ की शराब, महुआ चाय, बस्तरिया बिरयानी, गुड़ बोबो, मंडिया पेज, लांदा सहित कुलअन्य 27 प्रकार के बस्तरिया व्यंजन भी खिलाया। राजेश ने बताया कि आदि महोत्सव में देश के 28 राज्यों से आए लोगों ने यहां अपने-अपने इलाके के प्रसिद्ध फूड का स्टॉल लगाया है। जिसमें छग. से एक मात्र बस्तरिया फूड का स्टॉल उसने लगाया है।

राजेश का कहना है कि उसके पिता पुलिस में थे, वर्ष 2005 में गांव के साप्ताहिक बाजार गए हुए थे, उस दौरान सलवा जुडूम का दौर था। नक्सलियों ने बाजार में ही अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद मां और 2 छोटे भाई-बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई । खेती-किसानी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद उसने बस्तर आने वाले टूरिस्ट को बस्तर की परंपरागत खाना बनाकर खिलाने लगा। वहीं मुंबई के ताज होटल में चापड़ा चटनी सहित अन्य व्यंजन भेजने का अवसर मिला, साथ ही दिल्ली के अलग-अलग समारोह में स्टॉल लगाकर बस्तर के व्यंजन परोसने का अवसर मिला, इससे बस्तरिया व्यंजन ने देश भर में एक पहहचान दिलाई।

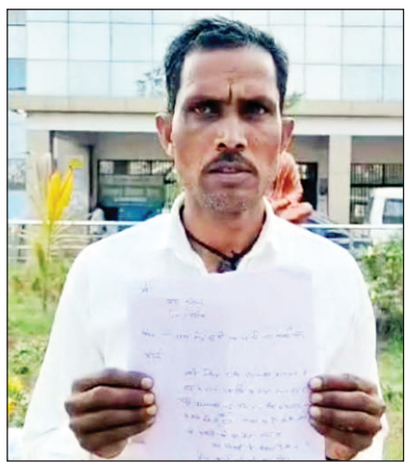

पूर्व सरपंच और सचिव पर फर्जी बिलों से राशि आहरण करने का आरोप

बालोद। बालोद जिले के ग्राम पंचायत (बी.) जामगांव के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. शिकायतकर्ता दयाराम देवांगन ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि पंचायत को 15वें वित्त आयोग से 32 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन पंचायत द्वारा 62 लाख रुपये व्यय किए जाने की जानकारी दी गई, जो समझ से परे है.

इसी तरह आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में ग्राम पंचायत (बी.) जामगांव की तत्कालीन सरपंच पुष्पा देवांगन और सचिव की सील व हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत करहीभदर के नाम से सामग्री खरीदने का बिल लगाकर राशि आहरित की गई है. ग्रामीण ने दोनों ही मामलों को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

अपर कलेक्टर ने दी प्रतिक्रिया- इस मामले में बालोद के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि यह एक गंभीर शिकायत है. उन्होंने बताया कि जनपद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अन्य पंचायत की खरीदी का भुगतान किसी अन्य पंचायत से किया गया है, तो यह जांच का विषय है और बिना विस्तृत जांच के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा.

पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटी लूटने का प्रयास: 100 आरोपियों पर मामला दर्ज

मनेन्द्रगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान केंद्र में घुसकर मतपेटी लूटने का प्रयास करने वाले 7 नामजद सहित 100 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना की शिकायत वनरक्षक योगेश्वर सिंह ने थाना खडगवां में दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 16 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान केन्द्र कमांक 26 अतिरिक्त भवन कटकोना में सैनिक भाल चन्द के साथ पीठासीन अधिकारी मुकदेव राम भगत एवं मतदान दल के कर्मचारियों के साथ जाने और चुनाव कराने के दौरान शांति व्यवस्था ड्युटी हेत लगा था।

चुनाव के बाद 17 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे, जब मतदान दल मतगणना कर रहा था, उसी समय बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसी दौरान, ग्राम कटकोना के आरोपी राम सिंह, राम अधार, दिनेश वियार, आरत, शिवकुमार, भजन, जगत और उनके लगभग 100 सहयोगी मतदान केंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित कर्मचारियों से अभद्र भाषा में गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने वनरक्षक योगेश्वर सिंह और सैनिक भालचंद पर हमला कर दिया तथा मतदान केंद्र का दरवाजा तोड़ते हुए चार आरोपी मतदान कक्ष में घुस गए।

उन्होंने मतपेटी लूटने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपियों ने सुरक्षाकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। जब पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी हस्तक्षेप करने पहुंची, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना खडगवां में अपराध क्रमांक 31/2025 के तहत धारा 191(2), 296, 351(2), 115, 132, 324(3), 333, 62 बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।

माता मावली मेले में शामिल हुए वन मंत्री कश्यप

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में आज से शुरू हुए ऐतिहासिक माता मावली मेले में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने माता मावली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और जिलेवासियों को मेले की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मंत्री कश्यप ने कहा कि मावली माता का आशीर्वाद बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की शक्ति प्रदान करता है। यह मेला सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। दूर-दूर से आए श्रद्धालु इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाते हैं। उन्होंने कहा,यहां के आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर अंचल के मड़ई-मेले आदिवासी संस्कृति, लोककला और परंपराओं के संरक्षण के केंद्र हैं। माता मावली मेला भी नारायणपुर जिले का ऐतिहासिक और ख्याति प्राप्त आयोजन है, जहां हर वर्ष स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दराज के सगे-संबंधी आते हैं और इस सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय इस मेले में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही, उन्होंने माता मावली के आशीर्वाद से जिले में चौतरफा विकास की कामना की। मंत्री कश्यप ने 02 मार्च को होने वाली अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के आधिकारिक टी-शर्ट का विमोचन भी किया। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस मैराथन में भाग लेने का आग्रह किया और इसे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया। मंत्री श्री कश्यप ने मेले में लगी विभिन्न सरकारी विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभिन्न दुकानों का अवलोकन किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सनकी पति ने पत्नी को लगाई आग, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह में आज सुबह एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को घर से कुछ दूर जिंदा जलाने के इरादे से आग लगा दिया. मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगिरों ने जब देखा तो महिला बुरी तरह से झुलसी हालत में मिली. राहगिरों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से पीड़िता के जले हुए चप्पल, माचिस और पट्रोल की खाली बोतल बरामद किया है और मामले में पीड़िता के आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता की पहचान भावना अग्रवाल, ढेलवाडीह सुतरा मार्ग के रूप में हुई, जिससे आरोपी गोपाल अग्रवाल (किराना व्यवसायी) ने 6 साल पहले शादी हुई थी. पीड़िता गोपाल की दूसरी पत्नी थी. इससे पहली पत्नी की मौत के बाद गोपाल ने दूसरी शादी की थी. लेकिन गोपाल को पहली पत्नी से भी कोई संतान नहीं मिला और दूसरी शादी को 6 साल होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिलने से वह अक्सर पीड़िता (भावना पर) आक्रोशित रहता था. अक्सर उससे मारपीट किया करता था.

तीन वर्ष से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला

कांकेर। चारामा से तीन वर्ष से लापता युवक दिनेश कुमार निषाद का शव आज बुधवार को उसके घर के पीछे पेड़ से लटका हुआ मिला। लापता युवक गांव कब पहुंचा? उसने आत्महत्या किया या उसकी हत्या हुई? पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार दिनेश की मां बुधवार सुबह करीब 3 बजे शौच के लिए बाहर निकलीं, तभी उन्होंने घर के दरवाजे पर लापता दिनेश का बैग पड़ा देखा। इसके बाद जब परिजन युवक को खोजने लगे, तो उसका शव खेत में स्थित एक पेड़ से लटका मिला। घटनास्थल पर पानी की बोतल, जूते और गमछा भी बरामद हुआ है। हालांकि युवक की मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार दिनेश निषाद ड्राइवर का काम करता था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यहआत्महत्या या हत्या है।

बीएससी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 24 से

कांकेर। शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुप्रतापपुर के बीएससी गणित एवं विज्ञान संकाय के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के समस्त नियमित, प्राइवेट एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है। 24 फरवरी को गणित द्वितीय वर्ष, समय 11:30 बजे होगी। वही 25 फरवरी को प्राणीशास्त्र द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, 25 फरवरी भौतिक शास्त्र तृतीय वर्ष, 1 मार्च को भौतिक शास्त्र द्वितीय वर्ष, 4 मार्च को वनस्पति शास्त्र द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और 3 मार्च को रसायन शास्त्र द्वितीय एवं 5 मार्च को रसायन शास्त्र तृतीय वर्ष की परीक्षा, सुबह 8 बजे से होगी। उक्त परीक्षा में सभी विद्यार्थी अपना प्रायोगिक रिकॉर्ड फ़ाइल एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री साथ में लाएंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी कारणवश परीक्षा में अनुपस्थित रहते है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

591 लीटर शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार उपायुक्त आबकारी जी.के भगत व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 17 फरवरी को रात्रि गश्त के दौरान आबकारी विभाग दुर्ग के द्वारा ग्राम नंदिनी खुन्दिनी, थाना नन्दिनी नगर में अवैध शराब के परिवहनकी सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 2 आरोपी राजकुमार सिंह पिता जोगेंदर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी-जुनवानी थाना सुपेला जिला दुर्ग के आधिपत्य से एक सफ़ेद रंग सेवरलेट बिट कार वाहन क्र. सीजी 04 केव्ही 7060 के पिछली सीट पर रखा 29 नग पेटी प्रत्येक पेटी में 48 नग पाव, कुल 1392 नग पाव रॉयल ब्लू व्हिस्की राज्य गोवा निर्मित विदेशी मदिरा जप्त किया गया। इसी प्रकार रंजीत सिंह पिता ओंकार सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी कैंप 1 आदर्श नगर थाना- छावनी के अधिपत्य के ग्रे रंग के आल्टो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 9418 के सीट व डिग्गी में रखा 29 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 नग पाव कुल 1392 नग पाव रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की विदेशी मदिरा जप्त किया गया।

शौचालय मरम्मत के लिए रिसाली में आयुक्त ने बनवाई चेक लिस्ट

भिलाई। सार्वजनिक शुलभ शौचालय के मरम्मत कार्य पर आयुक्त मोनिका वर्मा गंभीर है। उन्होंने घनी आबादी के बीच संचालित शौचालय के मरम्मत को ठीक से कराने चेक लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए है। आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि मरम्मत कार्य की जगह लीपा पोती होने पर निरीक्षणकर्ता जिम्मेदार होगा। आयुक्त मोनिका वर्मा वार्ड 32 स्थित शौचालय मरम्मत कार्य का निरीक्षण की। इस दौरान आयुक्त ने टॉयलेट शीट को क्रेक देख नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शौचालय मरम्मत कार्य का सुपरवाइजर चेक लिस्ट लेकर निरीक्षण करे। बाद में हस्ताक्षर कर चेक लिस्ट सब इंजीनियर को पुनः निरीक्षण करने दे। इसके बाद ही वे समीक्षा करेंगी। चेक लिस्ट में आयुक्त ने निर्धारित किये हैं कि शौचालय में टाइल्स की स्थिति, टॉयलेट शीट की स्थिति, केयर टेकर की उपलब्ध, पानी पाइप लाइन की स्थिति, दरवाजों की स्थिति, फ्लोर की स्थिति, दीवार की स्थिति, रंग रोंगन की स्थिति की जांच की जाये।

प्लेट मिल विभाग के कर्मचारी शिरोमणि पुरस्कार से हुए सम्मानित

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल विभाग में कर्म एवं पाली शिरोमणि पुरस्कार समारोह का आयोजन मुख्य महाप्रबंधक प्लेट मिल के बेहेरा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्तिकेया बिहेरा ने शिरोमणि पुरस्कार समिति द्वारा अनुशंसित पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। सितंबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए सहायक प्रबंधक श्री प्रीतम रामदास संडुगे को पाली शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया। इसी कड़ी में जुलाई 2024 के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑपरेशंस सेक्शन ए. अनिल, अगस्त 2024 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस रूपलाल साहू, सितंबर 2024 के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑपरेशंस सुभाष बांगड़े, अक्टूबर 2024 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑपरेशंस आलोक कुमार पुरोहित, नवंबर माह 2024 के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएट मेकैनिकल मेंटेनेंस रामनगीना जायसवाल, दिसंबर माह 2024 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑपरेशंस सेक्शन रूपेन्द्र कुमार साहू को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री बेहेरा ने शिरोमणी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी सुरक्षा को प्राथमिकता देकर कार्य करें।

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 : शांति, फिटनेस, सामुदायिक भावना और बस्तर की अछूती सुंदरता का उत्सव

रायपुर। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 शांति, फिटनेस, सामुदायिक भावना और बस्तर की अछूती सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। इस मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने के उद्देश्य से अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन 2 मार्च को नारायणपुर में किया जाएगा। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ, यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि आशा, एकता और बदलाव का प्रतीक बन चुकी है।

अबूझमाड़, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लंबे समय से नक्सली गतिविधियों के प्रकोप में रहा है। इस मैराथन के माध्यम से इस धारणा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सभी कौशल स्तरों के लोग एकता, प्रतिस्पर्धा और आपसी समझ की भावना के साथ भाग ले सकें। मैराथन में हाफ मैराथन (21 किमी), 10 किमी और 5 किमी की श्रेणियां शामिल होंगी, जिससे एथलीटों, पहली बार दौड़ने वालों और स्थानीय प्रतिभाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। अत्याधुनिक टाइमिंग सिस्टम, पेसर्स, चिकित्सा सहायता और हाइड्रेशन स्टेशनों के साथ, यह आयोजन सभी प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस आयोजन को आशा का प्रतीक बताते हुए कहा कि खेल की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाकर, हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं बल्कि शांति और एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहते हैं। अबूझमाड़ को अब माओवाद से नहीं, बल्कि यहां के लोगों की क्षमता और प्रतिभा से पहचाना जाएगा।

सफल आयोजनों के साथ बढ़ता उत्साह- मुख्य कार्यक्रम से पहले आयोजन समिति ने 5 जनवरी को 5 किलोमीटर की प्रोमो मैराथन आयोजित की, जिसमें पुरुष वर्ग में तीजू पुजारी, लक्ष्मण पोयाम और बीरसिंह सलाम विजेता बने, जबकि महिला वर्ग में सोमराई गोटा, रीना उइके और भूमिका देवांगन शीर्ष स्थान पर रहीं। इसके बाद 19 जनवरी को नारायणपुर में 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन हुई, जिसमें 800 से अधिक धावकों ने भाग लिया। इसमें पुरुष वर्ग में पुरकेश्वर लाल देशमुख, रस्सू कोरेस और बुधराम कुमेटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में मुस्कान कुशवाहा, भूमिका देवांगन और सोंबाई गोटा विजेता रहीं।

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की तैयारियां जोरों पर, 5,000 से अधिक प्रतिभागियों की होगी भागीदारी

प्रतिभागियों के लिए विशेष सुविधाएं- प्रतिभागियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मार्ग में सहायता केंद्रों की व्यवस्था होगी, जहां पीने का पानी, इलेक्ट्रोलाइट पेय, स्नैक्स, फल और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होंगे। धावकों के लिए रिकवरी/रेस्टिंग टेंट भी लगाए जाएंगे। लाइव ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रतिभागियों को रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त होंगे और मार्ग को एलईडी संकेतकों से स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा सहायता स्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रतिभागियों की सुरक्षा बनी रहे। अनुभवी पेसर्स प्रत्येक श्रेणी में धावकों को मार्गदर्शन देंगे, जिससे वे अपनी गति बनाए रख सकें और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मैराथन से पहले कुछ विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। 28 फरवरी को 'बैंड दायरा' द्वारा जादू बस्तर कॉन्सर्ट आयोजित होगा। 1 मार्च को एक भव्य ड्रोन शो होगा, साथ ही अबूझमाड़ मल्लखंब टीम द्वारा अद्भुत करतबों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक नृत्य, स्थानीय कला प्रदर्शनियां और बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेल के महत्व के साथ-साथ, यह मैराथन अबूझमाड़ की अनछुई सुंदरता और इसकी क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी और क्षेत्र के विकास में सहायक होगी।

नक्सल प्रभावित बीजापुर में वोटरों ने बनाया रिकार्ड

रायपुर। तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज संपन्न हो गया. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटरों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया. दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 30 जिलों के 43 विकासखंडों में मतदान हुआ. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में वोटरों की कुल संख्या 46 लाख 83 हजार 736 थी. राज्य चुनाव आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 26 हजार 988 पंच पद, 3 हजार 774 सरपंच पद, 899 जनपद सदस्यों के लिए वोट डाले गए. वहीं 138 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी वोटिंग कराई गई.

9738 पोलिंग बूथों पर हुई वोटिंग= दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 9 हजार 738 मतदान केंद्र बनाए गए थे. 43 विकासखंडों में बनाए गए 9738 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम थे. किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी तरह के हंगामे की खबर नहीं मिली. सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया.

नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में जमकर पड़े वोट= धुर नक्सल प्रभावित कटेकल्याण ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली.पखनाचुआं, बड़ेबेड़मा,बड़े लखापाल,सूरनार,धनीकरका, भूसारास, दुधीरास, एड़पाल,मोखपाल, माहराकरका अंदरूनी क्षेत्रों चिकपाल मारजुम जंगमपाल मतदान केंद्रों में वोटरों का उत्साह देखने लायक रहा. मतदान करने आए ग्रामीणों का कहना था कि वो गांव में बेहतर सुविधाओं के लिए वोट डाल रहे हैं. वोटिंग के लिए कई ग्रामीण तो 15 से लेकर 16 किमी दूर तक का सफर तय कर बूथ तक पहुंचे. ग्रामीणों का कहना था कि आज जो दिक्कत उनको है उनकी आने वाली पीढ़ी को नहीं हो इसके लिए वोट जरुरी है. मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सीआरपीएफ डीआरजी पुलिस बल सीएफ दंतेश्वरी महिला कमांडो ने भी अपना योगदान दिया.

महिला वोटरों का दिखा उत्साह= महासमुंद के जनपद पंचायत पिथौरा और बागबाहरा में महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर गांव की सरकार चुनने में अपना योगदान दिया. सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं. बागबाहरा विकासखंड के ग्राम अरंड के मतदान केन्द्र में 75 साल की लीलाबाई साहू ने वोट डाला. ग्राम मोहंदी की 88 साल की बैशाखीन कमार ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया. वोटिंग के लिए पहुंची महिलाओं ने कहा कि गांव की सरकार चुनने का मौका आया है. अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना उनका हक है.

कहां पड़े कितने फीसदी वोट

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कुल 77.47% मतदान हुआ.
कांकेर में 67.8% हुआ.
भानुप्रतापपुर 66.17% मतदान हुआ.
दुर्गुकोंडल 7%न्न मतदान हुआ.
कुल प्रतिशत 67.81% मतदान हुआ.
धमतरी के कुरुद में 70.12 फीसदी मतदान हुआ.
दुर्ग में 87.24 % प्रतिशत हुआ मतदान.
बलरामपुर विकासखंड में 83 फीसदी मतदान.
रायपुर में 77.6 फीसदी हुआ मतदान.
धमतरी के कुरुद में 83 फीसदी हुआ मतदान.
दूसरे चरण में इन विकासखंडों में पड़े वोट
विकासखण्ड बिल्हा(बिलासपुर)
विकासखण्ड पेण्ड्रा(गौरेला पेण्ड्रा मरवाही)
विकासखण्ड लोरमी(मुंगेली)
विकासखण्ड नवागढ़(जांजगीर चांपा)
विकासखण्ड मालखरौदा(सक्ती)
विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा(कोरबा)
विकासखण्ड खरसिया और धरमजयगढ़(रायगढ़)
विकासखण्ड बिलाईगढ़(सारंगढ़-बिलाईगढ़)
विकासखण्ड रामानुजनगर और प्रेमनगर(सूरजपुर)
विकासखण्ड बलरामपुर(बलरामपुर)
विकासखण्ड सीतापुर एवं मैनपाट(सरगुजा)
विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़(मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर)
विकासखण्ड जशपुर, मनोरा ,दुलदुला और कुनकुरी(जशपुर)
विकासखण्ड धरसींवा एवं तिल्दानेवरा(रायपुर)
विकासखण्ड कसडोल(बलौदाबाजार)
विकासखण्ड छुरा(गरियाबंद)
विकासखण्ड पिथौरा एवं बागबहरा(महासमुन्द)
विकासखण्ड कुरूद(धमतरी)
विकासखण्ड पाटन(दुर्ग)
विकासखण्ड बालोद(बालोद)
विकासखण्ड छुरिया(राजनांदगांव)
विकासखण्ड खैरागढ़(खैरागढ़ छुईखदान गण्डई)
विकासखण्ड मोहला(मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी)
विकासखण्ड बोड़ला एवं पण्डरिया(कबीरधाम)
विकासखण्ड फरसगांव एवं माकड़ी(कोण्डागांव)
विकासखण्ड बस्तर एवं लोहण्डीगुड़ा(बस्तर)
विकासखण्ड भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल(उत्तर बस्तर कांकेर)

संक्षिप्त समाचार

सरदार सुरजीत सिंह भाटिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह

रायपुर। राजनांदगांव के प्रतिष्ठित नागरिक सरदार सुरजीत सिंह भाटिया के निधन पर शोक व्यक्त करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा. रमन सिंह व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सिविल लाइन रायपुर स्थित उनके निवास स्थान पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। उनके पुत्र बलदेव सिंह भाटिया (पप्पू भाटिया), नीलू भाटिया एवं परिजनो से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। समाजसेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए डा. रमन सिंह कहा कि वे काफी सरल व सहज इंसान थे। एक परिवार के बुजुर्ग की तरह उनका हमेशा स्नेह मिला। रायपुर के अलावा राजनांदगांव,कवर्धा से आए स्नेहीजन भी इस मौके पर उपस्थित थे।

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की दो लोगों की हत्या, मुखबिरी का शक

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने दो लोगों की हत्या कर दी है. बुधवार शाम को बारसूर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनके गांव टोडमा में ग्रामीणों की हत्या की गई. अस्थायी अतिथि शिक्षकों की हत्या = पुलिस ने बताया कि जिन दो लोगों की हत्या हुई है, उनमें बामन कश्यप की उमर 29 साल और अनीस राम पोयाम की उम्र 38 साल है. बामन कश्यप एक सरकारी स्कूल में %शिक्षा दूत% यानी अस्थायी अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा था.

पुलिस का मुखबिर होने का लगाया आरोप = पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन की आमदई एरिया कमेटी के एक पर्चे में ग्रामीण पर पुलिस मुखबिर के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया है. पर्चे में आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2024 के थुलथुली मुठभेड़ से पहले बामन कश्यप नाम के ग्रामीण ने दंतेवाड़ा पुलिस को माओवादियों के आंदोलन के बारे में जानकारी दी थी.

नारायणी ने वृद्धजनों के साथ मनाया स्थापना दिवस, संग्रहालय भी बढ़ा

रायपुर। सामाजिक - साहित्यिक क्षेत्र की अग्रणी संस्था नारायणी साहित्यिक संस्थान ने बुधवार को अपना 8वां स्थापना दिवस वृद्धजनों के साथ मनाया। संस्था की अध्यक्ष डॉ. मृणालिका ओझा ने बताया कि ग्रास रूट सोसायटी द्वारा सुंदर नगर में संचालित प्रशामक देख - रेख गृह (वृद्धाश्रम) में मनाया। इस अवसर पर वृद्धजनों को न केवल भोजन कराया गया अपितु राशन सामग्री, डिशवॉश सहित संस्था में रहने वाले भवतोष, बुधराम जैसे अस्वस्थजनों के लिए चिकित्सकीय सामग्री भी प्रदान की गई।

कैंसर यूनिट, मेकाहारा के पास संचालित चरामेति नि= शुल्क भोज सेवा का आयोजन भी किया गया। विभिन्न भाषा बोलियों के संग्रहालय हेतु तेलुगू (इनाडु , आंध्र ज्योथि)एवं उर्दू भाषा के समाचार पत्र सियासत सहित उर्दू लिपि में सिंधी भाषा के भजनो की पुस्तक रसालो सचल सरमस्त भी प्राप्त हुई। ज्ञातव्य है कि इस संग्रहालय में 60 से ज्यादा भाषाओं के करीब 150 से कैलेंडर एवं अनेक भाषाओं के समाचार पत्र, पत्रिकाएं संग्रहित है। इस अवसर पर राजेंद्र ओझा, किशोर, ह्रषिक, किअंश, पार्थ एवं देख रेख गृह की ममता शर्मा, ज्योति आदि उपस्थित थे।

मार्कण्डेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर होगा भव्य आयोजन

रायपुर। महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त राजधानी के शिवालयों में तैयारियों को लेकर उत्साह और उमंग का दृश्य सबको भक्ति और श्रद्धा से आप्लावित कर रहा है। राजधानी के अनेक प्राचीन शिवालयों में से एक पेंशन बाड़ा और टैगोरनगर से लगी आवासीय कॉलोनी विवेकानंद नगर में स्थित %मार्कण्डेय महादेव मंदिर% की ख्याति से सभी अवगत हैं, जहाँ इन दिनों महाशिवरात्रि पर्व पर तैयारी में मंदिर संचालन समिति के पदाधिकारी और सदस्य सतत जुटे हुए हैं। इस दिन मंदिर में दिन-रात पूजन-अर्चन के साथ ही भक्ति-संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

रायपुर के पेंशन बाड़ा और टैगोरनगर से लगी आवासीय कॉलोनी विवेकानंद नगर में स्थित यह मंदिर सम्पूर्ण शिव परिवार, मार्कण्डेय एवं यमराज सहित विभिन्न अवतारों का प्रतिष्ठित मंदिर है। कभी मंदिर के पास ही बिल्व-पीपल-बरगद का एक विशाल युग्म वृक्ष हुआ करता था, जो कतिपय भूमाफियाओं की लालच का शिकार होकर नष्ट हो गया। यहाँ नाग-नागिन का एक जोड़ा भी रहता था, जो संभवत= भू-माफियाओं द्वारा की गई तोडफ़ोड़ के बाद काल कवलित हो गया। देखने वालों ने तो शिव पिंडी से लिपटे इस निरापद नाग-नागिन के जोड़े का दर्शन भी किया है! कहा जाता है कि जब यह आवासीय कॉलोनी अपना स्वरूप ही नहीं ले पा रही थी, तब कॉलोनी के मूल ले-आउट के अनुरूप इस अद्भुत मंदिर की स्थापना की गई जिसका लोकार्पण सन् 1966 में परमविदुषी सरोजबाला ने किया था। वर्तमान में इस मंदिर में श्रीराम दरबार और श्रीराधाकृष्ण के साथ ही पवनसुत हनुमान के विग्रह भी विराजित हैं।

महंत कॉलेज के वार्षिकोत्सव में संबलपुरी नृत्य की धूम

रायपुर । स्थानीय गांधी चौक स्थित महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मंथन-2025 में उड़ीसा के संबलपुरी नृत्य और फनी डांस ने जलवे बिखेरे, तो वही गणेश वंदना और सोलो डांस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बदौलत जमकर तालियां बटोरी । रविंद्र मंच कालीबाड़ी में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रायपुर दक्षिण के विधायक श्री सुनील सोनी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने की।

कार्यक्रम में शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिवारी, सचिव श्री अनिल तिवारी, श्री महेंद्र अग्रवाल महासचिव जैतुसाव मठ विशिष्ट अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थित रही । महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. देवाशीष मुखर्जी, सांस्कृतिक प्रभारी डॉ. अनुपमा जैन, क्रीड़ा अधिकारी श्री विजय शर्मा, डॉ. किरण अग्रवाल, डॉ श्वेता शर्मा, प्रो. प्रीतम दास सहित कई विशिष्ट जनों की विशेष उपस्थिति रही । आयोजन में महाविद्यालय

का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्राचार्य डॉ. मुखर्जी ने कहा कि महाविद्यालय अपने 25 वर्षो के सर्वोत्तम समय से गुजर रहा है, जहाँ पढ़ाई, शोध एवम खेलकूद के सभी क्षेत्र में महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय में अपना अलग स्थान बनाने में कामयाब हुआ है । मुख्य अतिथि सुनील सोनी ने कहा कि यह महाविद्यालय अब रायपुर का प्रसिद्ध महाविद्यालयों के श्रेणी में सम्मिलित हो चुका है । अब इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गयी है ।

खत्म हो रहे परंपरागत बाजार पर चेंबर चिंतित, आगामी बजट में प्रावधान की मांग

रायपुर =छत्तीसगढ़ बजट की तैयारी में सरकार जुट गई है. मुख्यमंत्री विभागों की अलग-अलग दिन बैठक लेकर समीक्षा कर रहे हैं. साथ ही कई वर्गों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर संबंधित विभाग के मंत्रियों से मुलाकात की है. इस बीच चेंबर ऑफ कॉमर्स बजट को लेकर क्या सोचता है उन्होंने इसके लिए क्या सुझाव दिए हैं.इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने ईटीवी भारत को दी.

पुराने बाजार को जीवित करने का हो प्रावधान: वहीं छत्तीसगढ़ बजट को लेकर अमर पारवानी ने कहा कि ग्रोथ सेंट्रिक बजट होना चाहिए. सरकार चाहे जो भी बजट इंफ्रा को लेकर आया .अंदर सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए. उस जीडीपी और व्यापार बढ़ता है. यह पॉजिटिव

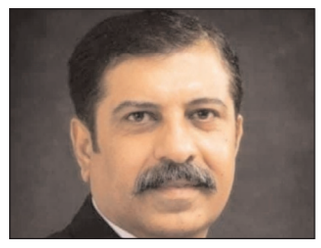

वातावरण बनाकर चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति काफी अच्छी है.वहीं बजट को लेकर चेंबर ने कुछ सुझाव भी दिए गए हैं.

आज हमारे परंपरागत बाजार समाप्त होते जा रहे हैं. उन्हें बचाने के लिए बजट में प्रावधान का सुझाव दिया गया है. गोल बाजार ,सराफा बाजार, बंजारी रोड बाजार यह हमारे पुराने परंपरागत बाजार हैं. इस तरह के बाजार सिर्फ रायपुर में ही नहीं. बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला और तहसील में हैं. जो आज धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं. इसे जीवित करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए - अमर परवानी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

बाजार में सुरक्षा के हो पर्याप्त इंतजाम =इसे कैसे जीवित किया जाए इसे लेकर कुछ सुझाव भी चेंबर के द्वारा दिए गए हैं. इसके अंतर्गत इन परंपरागत बाजार क्या सुवस्थित करना. महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, उचित पार्किंग व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था सहित अन्य सुविधा इन बाजारों में देने की मांग चेंबर में की है. 7 दिन बाजारों की सुरक्षा को लेकर भी उपाय किए जाने पर बजट में जोर देने की बात अमर परवानी ने कही. उन्होंने कहा कि इन परंपरागत बाजारों में भी फायर फाइटर सिस्टम लगाए जाने चाहिए, जिसे हादसे के दौरान बाजारों को सुरक्षित किया जा सके.

चिल्ड्रेन बैंक का नोट दुकान में चलाने की कोशिश, युवक हमला करके फरार

धमतरी। धमतरी के आमातालाब रोड में डेली नीड्स दुकान में दो दिन से कार में कुछ युवक पहुंच रहे थे.ये युवक नकली नोट देकर सामान खरीद रहे थे. इस दौरान जब दुकान संचालक ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने दुकानदार पर चाबी से हमला किया और भाग गए. जिसकी शिकायत कोतवाली थाना में की गई है.

क्या है मामला = जानकारी के अनुसार आमातलाब रोड निवासी विनायक ध्रुवंशी ने थाना सिटी कोतवाली में आवेदन देते हुए बताया कि उनका डेली नीड्स और चंदन आटा चक्की के नाम से दुकान है. 19 फरवरी को सामान खरीदने के लिए 2 युवक नकली नोट देने लगे. जब विनायक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग खड़े हुए.

युवक हमला करके फरार =अगले दिन फिर 20 फरवरी को युवक उनकी दुकान पर पहुंचे. इसके बाद उनके पास एक युवक आया.जिसने चिल्ड्रेन बैंक का पचास रुपया का नोट दुकानदार को दिया.इस दौरान जब दुकानदार ने युवक को पकड़ा तो दूसरा युवक भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर दुकानदार से मारपीट करनी शुरु की.इससे पहले कि दुकानदार दोनों को पकड़ता एक युवक ने विनायक के गले के पास वार किया और भाग गया.

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की कही बात = जब लोगों ने विनायक की आवाज सुनी तो दुकान में इकट्ठा हुए.तब तक दोनों युवक कार से भाग गए. अब लोगों ने नकली नोट देकर हमला करने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मरई ने कहा कि शिकायत मिली है. शिकायत की जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

13 पीओएस एजेंट गिरफ्तार, म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम बेचने का आरोप

रायपुर। सायबर क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में रायपुर रेंज के साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की अंजाम दिया है. पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 पीओएस एजेंट को गिरफ्तार किया. पुलिस की ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन साइबर शील्ड%% के तहत की गई.

ऑपरेशन साइबर शील्ड%%= अब तक पुलिस ने इस मामले में 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि इनके द्वारा जारी सिम यूनाइटेड अरब, अमीरात, श्रीलंका नेपाल म्यांमार में इस्तेमाल हो रहे हैं. पुलिस को इस बात की सूचना जांच के दौरान मिली. अपराध मैं उपयोग किए गए 7063 सिम कार्ड 590 मोबाइल फोनों की पहचान की जा चुकी है. आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. आगे की जांच रेंज साइबर थाना रायपुर की ओर से की जा रही है.

ऐसे किया फर्जीवाड़ा= ऐसे मामलों में साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर शील्ड%% चलाया जा रहा है, दोषियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है. अब तक ऐसे 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में

बताया है कि नया सिम लेने और सिम पोर्ट कराने में कस्टमर का डबल थंब स्कैन, आई ब्लिंक कर ई केवाईसी के माध्यम से अतिरिक्त सिम चालू करते थे. जिस कस्टमर के पास आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी होती थी उसका विवरण स्वयं ही वेरीफाई कर ई केवाईसी के माध्यम से अतिरिक्त सिम चालू करते थे. इस तरह से आरोपी इस सिम को म्यूल अकाउंट के रूप में ब्रोकर संचालक को बेचते थे, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है

धोखाधड़ी में शामिल हैं कई जिलों के लोग= पकड़े गए आरोपियों में कुलवंत सिंह छाबड़ा और हेमंत साहू राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं. अजय मोटघरे भी राजनांदगांव का रहने वाला है. ओम आर्य मुंगेली, चंद्रशेखर साहू रायपुर, पुरुषोत्तम देवांगन दुर्ग, रवि कुमार साहू दुर्ग, रोशन लाल देवांगन दुर्ग, शुभम सोनी दुर्ग का रहने वाला शामिल है. आरोपियों में के. वंशी दुर्ग, त्रिभुवन सिंह सुपेला, अमर राज केसरी भिलाई और विक्की देवांगन पोलसाय दुर्ग का रहने वाला शामिल है.

कांग्रेस की हार का सेहरा बांधेगा कौन, शीर्ष नेतृत्व बोला जवाबदेही तय होनी जरुरी

रायपुर। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंचायत से लेकर रा'य मुख्यालय तक और रा'य मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात कही है. नए कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी की होने वाली हार के लिए अब रा'यों के प्रभारी और रा'य के बड़े नेता ही जिम्मेदार होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी. जब किसी को कोई जवाबदेही दी जाती है उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल तय होती है.इस जिम्मेदारी से कोई हट नहीं सकता. अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली दरबार के आलाकमान ने आदेश तो जारी कर दिया.लेकिन इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हुई करारी हार के बाद किन पर गाज गिरेगी ये तय होना बाकी है.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घट रहा जनाधार = छत्तीसगढ़ में 202× के बाद से लगातार कांग्रेस का आधार घटता जा रहा है. 202× अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मजबूत मानी जाने वाली सरकार का तख्ता पलट हो गया. इस बड़ी हार का जिम्मेदार कौन होगा ये तय होना बाकी है. अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का आदेश चला तो

निश्चित तौर पर 2023 वाली हार के लिए किसी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ना तय है.इसके बाद छत्तीसगढ़ में नए नेतृत्व को लेकर भी मंथन हो सकता है. क्योंकि अब कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीति कठिन होती जा रही है क्योंकि साल दर साल हार कांग्रेस के लिए सौगात बन चुकी है.

2024 में हार का जिम्मेदार कौन ?= विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस खुद को संभाल नहीं पाई. बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया तो कांग्रेस ने 50-50 कह दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साथ तौर पर कह दिया था कि इस बार बीजेपी 400 पार का नारा देकर के आई है लेकिन छत्तीसगढ़ में आधी सीटों से कम पर ही हम उन्हें समेट देंगे. लेकिन जब परिणाम आए तो 2019 में जीती हुई बस्तर की सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई.अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था लेकिन वो फेल हो गया.कमजोरी किसकी ओर से हुई और 2024 के हार का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये भी एक बड़ा सवाल है.2025 में नगरीय निकाय में ध्वस्त हुआ कांग्रेस का किला = 202× में विधानसभा के चुनाव में करारी शिकायत कांग्रेस को मिली और सरकार चली गई.202× में छत्तीसगढ़ कांग्रेस इकाई के नेता एकजुटता की बात दोहराते रहे लेकिन आखिर समय में सब बिखर गया.इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की बात हुई लेकिन 2019 में बस्तर की जीती हुई सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली गई. फिर 2025 में 202× और 2024 में हुई हार को जीत की सौगात में बदलने को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा किया गया. लेकिन कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई. 2025 में 10 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस किसी में भी खाता ना खोल सकी. जो गढ़ कभी कांग्रेस का झंडा उठाकर खड़े थे,वहां ना संगठन था ना ही कार्यकर्ता.

हार के बाद कांग्रेस का आया बयान = नगरीय निकाय चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के संचार मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हमने जनता के बीच जाकर काम किया था. लेकिन उसके बाद भी हमें हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन यह जनता का फैसला है जनता ने जो जनमत दिया है हम उसे मानकर चल रहे हैं. जनता के लिए हम हमेशा सेवा करते रहेंगे. लेकिन सवाल यह है कि हार के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का आदेश सेवा करने के लिए पार्टी कार्यालय में किस चेहरे को रहने देगा यह बड़ा सवाल है.बीजेपी ने हार पर ली चुटकी = वहीं छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की हार पर बड़ी चुटकी ली.अरुण साव के मुताबिक हार का असर कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगा. पार्टी के अंदर में अब लड़ाई होगी. ये लड़ाई आगे तेज होगी. कांग्रेस को जनता से कोई लेना-देना नहीं है इन्हें सिर्फ एक परिवार की चिंता है. अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपने-अपने लिए लड़ेंगे. क्योंकि कांग्रेस शून्य की ओर अग्रसर है. वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का जनमत, जनाधार और जमीन खिसक चुका है. पार्टी के शीर्ष इकाई कार्रवाई करने की बात जरूर कह रहे हैं।

जंग रोकने के बहाने डोनाल्ड ट्रम्प बदल रहे समीकरण?, पीछे सिर्फ पूंजी ही प्रधान

राजेश बादल

अमेरिका के मंच पर डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरी बार प्रगट होने के साथ ही संसार के समीकरण बदलने लगे हैं। इन समीकरणों के पीछे सिर्फ पूंजी ही प्रधान है। तमाम लोकतांत्रिक सिद्धांत, आदर्श और नैतिक मूल्य अब गुजरे जमाने के अध्याय हैं, जिन्हें नया वैश्विक समाज नहीं पढ़ना चाहता। अपने राष्ट्रहित के बहाने राष्ट्राध्यक्ष अधिनायक में तब्दील हो रहे हैं और अवाम उन्हें असहाय सी देख रही है। हालांकि यह सिलसिला कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद भी करोड़ों लोग इसके समर्थक दिखाई देते हैं। यह विडंबना है।

आज का अमेरिका अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे केवल अमेरिका को लाभ या नुकसान होगा, बल्कि अनगिनत छोटे-मंझोले मुल्कों को अपना रवैया और रीति-नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। ताजा उदाहरण रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिए अमेरिकी पहल है।

मंगलवार को सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा व्हाइट हाउस के मध्यपूर्व प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का विस्तृत ब्यौरा अभी नहीं आया है, पर यह स्पष्ट है कि यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव काम आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुधवार को इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं।

पर जो संकेत मिले हैं, उनसे पता लगता है कि जेलेंस्की अब बेहद दबाव में हैं। उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति को समझना होगा कि उधार के सिंदूर से वे सुहाग की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधियों से जेलेंस्की की मुलाकात ही सबूत है कि अब इससे जेलेंस्की की हैसियत क्या हो गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद रोक दी है।

इसके बाद यूरोप भी यूक्रेन का साथ देने के मुद्दे पर बंट रहा है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमेन्युअल मैक्रों ने सोमवार को खास यूरोपीय देशों की जो बैठक बुलाई थी,उससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन को समर्थन के मसले पर यूरोपीय देशों में आम राय नहीं है। मैक्रों आक्रामक थे और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे।

इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी ढपली से अलग धुन निकाली। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए उनका देश अपनी सेनाएं तैनात करने जा रहा है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने इससे किनारा कर लिया। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर कहा कि यूक्रेन के मामले में यूरोप और अमेरिका की नीति एक ही होनी चाहिए।

बैठक के बाद ट्रम्प ने मैक्रों से सीधे बात की। इसके बाद मैक्रों के तेवर भी ठंडे पड़ गए। इस तरह यूरोप अब अमेरिकी ऑर्केस्ट्रा पर नाचने के लिए बाध्य है। ब्रिटेन पसोपेश में है। उसने यूक्रेन में सेना तैनात करने का फैसला तो ले लिया, मगर उस पर अमल करना आसान नहीं है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि नाटो की सदस्यता अब यूक्रेन को मिलने से रही।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने तो तीन दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता संभव नहीं है। यानी यही बात तो रूस यूक्रेन को समझा रहा था कि वह नाटो में शामिल होगा तो नाटो सेनाओं को यूक्रेन के रास्ते रूस की सीमाओं पर तैनाती का मौका मिल जाएगा, तब जेलेंस्की की समझ में आया नहीं। अब लौट के बुद्धू घर को आए वाली तर्ज पर जेलेंस्की हाथ मल रहे होंगे।

लब्बोलुआब यह कि इस मामले में हारा हुआ खिलाड़ी यूक्रेन ही है। आपको याद होगा कि इसी पन्ने पर मैंने अनेक बार लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सियासत में आने से पहले विदूषक थे और वे अपने देश को विनाशकारी आग में झोंक रहे हैं। जब यह जंग खत्म होगी तो यूक्रेन हाथ झारि के चले जुआरी वाली स्थिति में होगा।

मैंने 9 जुलाई, 2024 को इसी पन्ने पर प्रकाशित अपने लेख में लिखा था कि यूक्रेन कुछ वर्षों से यूरोपीय और पश्चिमी देशों का खिलौना बन गया है। ढाई साल से जारी जंग इसका प्रमाण है। यूक्रेन यह सिद्धांत समझने के लिए तैयार नहीं है कि पड़ोसी से कितने ही शत्रुतापूर्ण संबंध हों, लेकिन जब घर में आग लगती है तो बचाता भी पड़ोसी ही है।

इसके पीछे मंशा यह होती है कि पड़ोसी अपना घर भी तो आग से बचाना चाहता है। लेकिन हास्य अभिनेता रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं।

ट्रंप, मोदी और चाणक्य नीतिः प्रतिद्वंद्वी को आदर्श बताकर उसे निहत्था करना सर्वोत्तम कूटनीति

दीपक वोहरा

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे चौथे विदेशी नेता थे, जो दूसरी पारी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं। उनसे पहले अमेरिका के कट्टर सहयोगी इस्त्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के राजा ट्रंप से मिल चुके हैं, जो गाजा पट्टी से निकाले जाने वाले फलस्तीनियों को अपने यहां लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो इस बार की मुलाकात में क्या खास बात रही? इससे यह संकेत मिला है कि वर्ष 2025 में भारत एक आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर वैश्विक नेता के रूप में पहचाना जाएगा।

हालांकि, दो दिग्गज वैश्विक नेताओं की यह मुलाकात पूरी तरह से व्यापार को लेकर थी। व्यापार एक ऐसा विषय है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके भारतीय गुजराती समकक्ष, दोनों पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फोकस के क्षेत्र होंगे-प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, लचीली आपूर्ति, ऊर्जा (विशेष रूप से छोटे परमाणु रिएक्टर)। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत अमेरिका से बहुत सारा तेल और गैस खरीदेगा, जिसकी भारत को जरूरत है और अमेरिका के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से सीखा है कि देश को सर्वोपरि रखना कितना महत्वपूर्ण है और वह भी यही कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा करना और उसे आदर्श बताकर निहत्था करना चाणक्य की प्राचीन रणनीति है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को हल करने की पहल के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, दोनों से समाधान खोजने का आग्रह किया। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा चीन था। हाल ही में बीजिंग ने अमेरिका, भारत तथा सामान्य रूप से विश्व को दी जाने वाली धमकियों में नरमी बरती है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ते हैं।

अपने शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने बांग्लादेश की हिंसा और शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद वहां अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की आलोचना की थी। ट्रंप अपने देश को वैश्विक संकटों से अलग रखना, न कि नए संकटों में उलझाना चाहते हैं। इसके अलावा, कमजोर बांग्लादेश अमेरिका से कोई भी सार्थक वस्तु नहीं खरीदता, इसलिए व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप को वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। लगता तो यही है कि हिलेरी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस के करीबी मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता से हटा देंगे। भारत और अमेरिका, दोनों इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इसलिए संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि आतंकवाद के वैश्विक संकट से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरे देखे द्विपक्षीय संयुक्त बयानों में यह पहला ही है, जिसमें अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा (अंतिम दो पाकिस्तान में स्थित हैं) सहित आतंकी गुटों का विशेष उल्लेख किया गया है। 'हमारे नागरिकों' को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की साझा इच्छा के चलते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी और पूर्व पाकिस्तानी सेना कप्तान तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की घोषणा की। संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान से आग्रह किया गया कि वह 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमलों के दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उसके भू-भाग का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न किया जाए।

भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हुए। इस तरह अमेरिका ने भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण के साथ एक प्रमुख रक्षा साझेदार और एक प्रमुख क्वाड साझेदार के रूप में मान्यता दी। जाहिर है, नरेंद्र मोदी की यह यात्रा रक्षा सहयोग पर केंद्रित थी, जिसमें अमेरिका भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार कर अंतर-संचालन और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं की विदेशी तैनाती का समर्थन करते हैं और उसे बनाए रखेंगे। साफ है कि दोनों देश इस अहम क्षेत्र में अपने अड्डे साझा कर सकते हैं। अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद के लिए संयुक्त समुद्री सेना नौसैनिक टास्क फोर्स में भविष्य में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भारत को अमेरिका का खुला समर्थन स्पष्ट रूप से चीन के कारण है। इस यात्रा से अमेरिका-भारत ट्रस्ट की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत तेल एवं गैस (ऊर्जा) के लिए भूखा है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। भारत ने अमेरिका से अवैध भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया, और यात्रा से ठीक पहले 104 भारतीयों को वापस भेजने के तरीके पर भारत में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को देखते हुए ट्रंप को अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया।

ट्रंप चाहते थे कि भारत विशिष्ट अमेरिकी उत्पादों पर अपने सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करे व भारत ऐसा कर रहा है। ट्रंप ने माना कि नरेंद्र मोदी उनसे भी बेहतर सौदेबाज हैं। इसके अलावा, अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं के आव्रजन व?आसान वीजा प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के बारे में भी चर्चा हुई। यात्रा से कुछ दिन पहले, अमेरिकी विदेश विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया कि कैसे अमेरिकी डार्क स्टेट ने 2019 में नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी जीत से भयभीत भारतीयों को शामिल करके भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2025 को भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में याद किया जाएगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

अनेकों को अपने शरणागत हो जाने पर देश से निकाला, वा अमुक 2 स्थान में नजरबन्द रक्खा, तथा पुनः अपने राज्य में तपश्चर्या, पवित्रता, दयाभाव एवं सत्य की स्थापना की- यह इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य है जो परकीया भाषा द्वारा प्रकट किया गया है। साथ ही जुआ (मिथ्याभाषण) मद्यपान (मदान्धता) व्यभिचार (कामोपभोग) और हिंसा (वैर) तथा सुवर्ण (लोभ) इन पांच स्थानों में कलि नामक युग या कलह निवास करता है - यह परमोपयोगी उपदेश भी इस कथानक के उपसंहार से प्रकट कर दिया है।

इस तरह इम त्रिविध भाषा का सोदाहरण निरूपण करने के बाद पाठकों को यह बता देना आवश्यक समझते हैं, कि पुराणान्तरवर्ती प्रत्येक कथा को हमारे पूर्वोक्त लक्षणों के अनुसार किसी उचित श्रेणी में परिगणित करके तत्पश्चात् उसका वास्तविक तात्पर्य समझना चाहिये। जो लोग पुराणों की भाषाटीका में लिखे हुये अक्षरार्थों के आधार पर ऐसे सन्दर्भों को गप्पाष्टक बता कर अपनी मूर्खता का परिचय दिया करते हैं, उन लोगों को कुछ साहित्यशास्त्र का अर्थ-विचार अध्ययन करना चाहिए, जिससे अभिधार्थ से आगे बढ़कर लाक्षणिक और व्यञ्जक अर्थों के समझने की भी योग्यता हो सके ।

यास्काचार्य ने निरुक्त (7।1।3) में उक्त त्रिविध भाषायों को नामान्तर से स्मरण किया है। आप लिखते हैं कि - तास्त्रिविधा ऋच:, परोक्षकृता:, प्रत्यक्षकृता:, आध्यात्मिक्यश्च ।

अर्थात् - वेद की ऋचाएं तीन प्रकार की हैं (1) परोक्षकृत (2) प्रत्यक्षकृत और (3 आध्यात्मिक । सो आध्यात्मिकी को समाधि प्रत्यक्ष को लौकिकी और परोक्ष को परकीया कह सकते हैं।

क्रमशः ...

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दुनियाभर में भाषा एक ऐसा साधन है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। एक देश में कई मातृभाषा हो सकती हैं। भारत में ही 122 ऐसी भाषाएं हैं, जिनको बोलने वालों की संख्या 10 हजार से ज्यादा है। वहीं 29 भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें 10 लाख लोग बोलते हैं। भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, पंजाबी, अरबी, जापानी, रूसी, पुर्तगाली, मंदारिन और स्पैनिश बोली जाती हैं। विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए और कई मातृभाषाओं के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से प्रति साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की थीम, इतिहास और महत्व।वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पहली

बार इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी। बाद में वर्ष 2000 से विश्व भर में यह दिन मनाया जाने लगा।

जब 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया। पहला -पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उर्दू में देश की मातृभाषा घोषित किया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा अधिक होने के कारण उन्होंने बांग्ला को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया।

बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 21 फरवरी को उनका संघर्ष पूरा हुआ और बांग्लादेश की वर्षगांठ भी इसी दिन से मनाई जाने लगी।

भारत विविध संस्कृति और विभिन्न भाषाओं का देश है। 1961 की जनगणना के मुताबिक, भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल भारत में 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग-अलग है। हिंदी दूसरी सबसे लोकप्रिय मातृभाषा है। देश में 43 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, इसमें 12 फीसद द्विभाषी है।

कितना बदला निर्वासित शहर लाहौर?

रामचंद्र गुहा

कई साल पहले जब मैं खेल के सामाजिक इतिहास पर काम कर रहा था, तब मुझे 1955 में लाहौर में खेले गए एक टेस्ट मैच की कुछ समाचार रिपोर्टें मिलीं। यह मैच अत्यधिक उबाऊ था, जो भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए पांच मैचों की शृंखला के पांच ड्रॉ में से एक था। इसमें प्रति ओवर दो से भी कम रन बने थे। इस मैच को लेकर जो बात अधिक दिलचस्प थी, वह सामाजिक संदर्भ थी। 1947 के बाद यह पहला मौका था, जब लाहौर शहर को अपने बहुसांस्कृतिक अतीत को दोबारा प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इस टेस्ट के लिए कम से कम दस हजार टिकट भारतीय नागरिकों के लिए अलग रखे गए थे, जो मैच देखने हर सुबह वाघा बॉर्डर पार करके आते थे और उसी रात अमृतसर लौट जाते थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इसे 'विभाजन के बाद सीमा पार से सबसे बड़ा सामूहिक प्रवासन' कहा था।

टेस्ट मैच 29 जनवरी, 1955 को शुरू हुआ। अगले दिन डॉन अखबार में छपा कि जैसे ही स्टेडियम का दरवाजा खुला, औरतें, सिख, हिंदू और स्थानीय लोग दो से तीन फर्लांग या इससे भी अधिक लंबी कतारों में धैर्य और शालीनता से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था, मानो पूरा शहर अवकाश के मूड में था। सुबह-सुबह भीड़ की ऐसी हलचल शालीमार मेले की याद दिला रही थी, बस अंतर इतना था कि यहां भीड़ का आकार बड़ा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस भीड़ में 'सिख विशिष्ट थे और वे जहां भी गए, आकर्षण का केंद्र बने। हर जगह उनका शानदार स्वागत किया गया। उनमें से कुछ तो पुराने मित्रों से गले मिलकर रो पड़े।' डॉन अखबार ने जो खबर छापी थी, वह गुमनाम थी, लेकिन उसके लेखक की भावनाओं को विभाजन के दर्द से दूर रहे मद्रास के एक हिंदू पत्रकार ने यह कहते हुए दोहराया कि 'टेस्ट मैच के दिनों में हर जगह पाकिस्तानियों और भारतीयों के बीच अद्भुत भाईचारा देखा गया।'

मुझे मनन अहमद आसिफ की किताब 'डिसरप्टेड सिटी = वॉकिंग द पाथवेज ऑफ मेमोरी एंड हिस्ट्री ऑफ लाहौर' को पढ़ते हुए उन खबरों की याद आ गई। लेखक लाहौर में ही बड़े हुए थे, लेकिन 30 साल पहले उन्होंने यह शहर विदेश में पढ़ाई करने और वहीं काम करने के कारण छोड़ दिया था। हालांकि वह अक्सर अपने घर आते थे। उनकी इस पुस्तक का उद्देश्य 'बिना उस राष्ट्र-राज्य का बंधक बने इस शहर के विरासती इतिहास को बताना है।'

आसिफ अपनी कहानी की शुरुआत में कहते हैं, '1947 से पहले के लाहौर की विविधता हिंदू और सिखों के पलायन और पंजाब (भारत) के हिस्सों से मुस्लिम शरणार्थियों के आने के साथ खत्म हो गई।' वह आगे कहते हैं, 'विघटन के उस क्षण के बाद यह अपने ही अतीत से एक निर्वासित शहर बन गया।' आसिफ की किताब में क्रिकेट का जिक्र तो कुछ ही समय के लिए है और 1955 के लाहौर टेस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उनकी पुस्तक उन चार दिनों के शालीमार मेले की याद दिलाती है, जिसे चिरागान मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक समय लाहौर का प्रमुख त्योहार था, जो 16वीं सदी के सूफी संत शाह हुसैन के जीवन और विरासत के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। आसिफ अपनी किताब में लिखते हैं कि शाह हुसैन के विचार में 'उन लोगों की निंदा की जानी चाहिए, जो रूढ़िवादिता के समर्थक है, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, खुशी से नाचते-गाते हैं और अक्सर निर्वस्त्र रहते हैं।' शाह हुसैन के सबसे करीबी साथी या प्रेमी एक हिंदू थे और जिस मंदिर में दोनों को दफनाया गया, वह जगह 'हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए तीर्थस्थल के साथ एक वार्षिक उत्सव स्थल भी बन गया।' विभाजन के बाद उत्सव ने अपनी विविधता खो दी, जिसे पर्यवेक्षकों ने 1955 के लाहौर टेस्ट के दौरान देखा था।

मनन आसिफ की किताब उनके शहर और उसके समृद्ध अतीत के बारे में हमारी समझ विकसित करती है, साथ ही शहर से जुड़े पात्रों, जैसे दाता गंज बख्श, योद्धा रणजीत सिंह आदि के अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। आसिफ द्वारा उकेरे गए रेखाचित्र सूक्ष्म जानकारी तो देते हैं, लेकिन उनमें एक अपवाद रुडयार्ड किपलिंग का है, जिन्हें वह एक पक्षपाती साम्राज्यवादी के रूप में चित्रित करते हैं। दूसरी ओर, उनके उपन्यास 'किम' में उनकी युवावस्था के लाहौर और वहां के लोगों के संघर्ष का सहानुभूतिपूर्ण और गहराई से वर्णन किया गया है।

आसिफ की किताब 'डिसरप्टेड सिटी' से लाहौर की स्थापत्य कला की गहरी समझ मिलती है, जिसमें वहां की प्रसिद्ध इमारतों के बारे में बताया गया है। खंडहर या परित्यक्त मंदिर और गुरुद्वारे, जो आज भी मस्जिदों के साथ दिखाई देते हैं, इस बात को दर्शाते हैं कि इन धार्मिक स्थलों ने लाहौर की विरासत में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य अध्याय में आसिफ दर्शाते हैं कि 1947 से पहले लाहौर का अधिकांश आर्थिक जीवन हिंदू और सिख उद्यम द्वारा आकार लिया गया था।

एक विचारोत्तेजक दृश्य में आसिफ लिखते हैं कि 1970-80 के दशक में जब लाहौर तेजी से इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा था, उस दौरान वह स्कूल से घर जाते हुए अक्सर एक पुराने घर से गुजरते थे, जिसके किनारे पर देवनागरी अक्षरों में कुछ धुंधले शब्द लिखे थे। वह याद करते हुए कहते हैं, 'कई महीनों तक मैं सिर्फ उस लिखावट पर सरसरी निगाह डालकर आगे बढ़ जाता था। मैं लाहौर में देवनागरी नहीं पढ़ सका (न पढ़ना सीख पाया)। मैं जानता था कि देवनागरी लिपि 'हिंदू' थी और मेरी सामाजिक विज्ञान की किताब में जैसा बताया गया था, 'हिंदू' वह व्यक्ति था, जो मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था।'

इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मैं हिंदुत्व राज में रहने वाले हिंदू बच्चों के बारे में सोचने लगा, जिन्हें उनके अतीत और वर्तमान के बारे में विकृत जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में भारत को एक हिंदू देश के रूप में दिखाया गया है। इस बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को हिंदुत्व सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया है, जैसे कि सभी उम्र के हिंदुओं से सभी मुसलमानों पर अविश्वास करने का आग्रह किया जाता है।

अपनी पुस्तक में एक जगह आसिफ बताते हैं कि कैसे एक बार मेला चिरागान और वसंत जैसे लोकप्रिय त्योहारों को सैन्य तानाशाह जिया-उल-हक द्वारा प्रचारित वहाबी इस्लाम के सिद्धांतों के साथ संघर्ष करने की वजह से बंद कर दिया गया था। 1980 और उसके बाद के पाकिस्तान में 'खुशी मनाना और सामूहिकता संदिग्ध गतिविधियां बन गईं।' ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदूवादी भारत भी

आज का इतिहास

1613- माइकल रोमारोव रूस के जार बने और तभी से वहाँ रोमानोव वंश का शासन स्थापित हुआ।
1707- औरंगज़ेब की मौत अहमदनगर में हुई।
1795- डचों ने सीलोन, श्रीलंका अंग्रेज़ों को सौंप दिया।
1842- अमेरिका में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया गया।
1848- कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया।
1907- अंग्रेज़ी भाषा के कवि आडेन का जन्म।
1914 - बर्दुन का युद्ध प्रारम्भ।
1916 - प्रथम विश्व युद्ध में फ़्रांस में बर्डन की लड़ाई भड़की।
1919 - बावारेवा के प्रधानमंत्री कुर्तरिजनर की हत्या म्यूनिख में हुई।
1925 - न्यूयॉर्कर मैगजीन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन।
1943 - ब्रिटेन नरेश जार्ज षष्ठ ने रूसियों को सम्मानित किया।
1946 - मिस्र में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन।
1948 - स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया।
1952- ढाका (उस समय पूर्वी पाकिस्तान) में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर तब गोलियां चलाईं जब वे बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। बाद में इस आधिकारिक दर्जा दिया गया और बांग्लादेश में इसके बाद से यह दिन भाषा आंदोलन के स्मारक के रूप में मनाया जाने लगा ।
1959 - प्रेस क्लब आफ् इंडिया की नई दिल्ली में स्थापना।
1963 - सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा पर हमला विश्वयुद्ध में बदल सकता है।
1973 - सिनाई रेगिस्तान में, इजरायली लड़ाकू विमान ने लीबिया अरब एयरलाइंस के विमान-114 को मार गिराया जिससे इसमें सवार 108 लोगों की मौत हो बई।
1974 - युगोस्लाविया ने संविधान स्वीकार किया।
1975 - राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इस्त्रायल की कड़ी निंदा की।
1981 - नासा ने सेटेलाइट कोमस्टर-4 का प्रक्षेपण किया।

अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं?

नीरज कुमार दुबे

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत ही बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि रेलवे ने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखा है। बड़ी खबर यह भी है कि लोग यह समझ चुके हैं कि रेलवे में सुधार की बातें सिर्फ खोखली हैं। बड़ी खबर यह भी है कि तमाम लोगों को इस बात का पक्का विश्वास हो चला है कि पर्वों-त्योहारों और छुट्टियों के समय टिकट खरीदने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचने तक रेल का सफर परेशान करेगा ही करेगा। बड़ी खबर यह भी है कि रेलवे स्टेशन पर या पटरी पर चलती ट्रेन के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाये, रेल मंत्री कभी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि दुर्घटना होने पर मुआवजे या जांच का ऐलान तुरंत ही करने वाले रेल मंत्री अपना इस्तीफा देना तो दूर कभी इस्तीफे की पेशकश तक नहीं करेंगे।

देखा जाये तो रेल मंत्री पद से अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि बात सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ही नहीं है। आप रेलवे को समग्र रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि कोई बड़ा सुधार कर पाने में अश्विनी वैष्णव पूरी तरह विफल रहे हैं। अगर महाकुंभ की ही बात कर लें तो भले रेल मंत्री ने प्रयागराज के लिए हजारों ट्रेनें चलाने के दावे किये हों लेकिन आप देशभर में सर्वे करा लें तो पाएंगे कि प्रयागराज के लिए ज्यादातर लोगों को ट्रेनों में टिकट मिले ही नहीं और जिनको टिकट मिले उनका सफर आरामदायक नहीं रहा। यही नहीं, हैरानी की बात यह भी रही कि प्रयागराज के लिए रेलवे की वेबसाइट और ऐप पर भले टिकट नहीं थे लेकिन मेकमाई ट्रिप जैसी ट्रैवल साइटों पर 500 रुपए की अतिरिक्ति फीस देकर उसी तारीख के रेलवे टिकट उपलब्ध थे। हम 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन 2025 तक रेलवे को इतना भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाये हैं कि उसकी ही वेबसाइट और ऐप पर सभी को कंफर्म टिकट मिल जायें। आज भी रेल यात्रियों को अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए वीआईपी कोटा या रेलवे कोटा लगवाने के लिए नेताओं और अधिकारियों से मदद मांगनी पड़ती है जोकि शर्मनाक है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के जांच के आदेश तो दे दिये गये हैं लेकिन सवाल उठता है कि पहले की घटनाओं की जांच रिपोर्टों का क्या हुआ? पिछली घटनाओं के लिए कौन लोग दोषी ठहराये गये, उन्हें कौन-सी कड़ी सजा हुई? क्या इसका विवरण कभी रेल मंत्री देश के सामने रखने का साहस जुटाएंगे? देखा जाये तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना का प्रमुख कारण था ऐन समय पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म का बदला जाना। यह ऐसी चूक है जिसकी वजह से पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं लेकिन रेलवे ने कभी सबक नहीं सीखा। जब रेलवे स्टेशन का प्रबंधन यह देख रहा था कि वहां भारी भीड़ उमड़ी हुई है तो प्लेटफॉर्म बदलने का फैसला टाल कर क्या घटना को रोका नहीं जा सकता था? बात सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी नहीं है। देश के तमाम शहरों से इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में लोग भारी भीड़ की वजह से चढ़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार के भी वीडियो वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि यात्री सिर्फ दरवाजों से ही नहीं बल्कि खिड़कियों से भी ट्रेन के भीतर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है कि लोग ट्रेनों में नहीं चढ़ पाने को लेकर तोड़फोड़ तक कर रहे हैं। जनता की यह नाराजगी साफ दर्शाती है कि महाकुंभ जैसे बड़े

आयोजन को लेकर रेलवे की ओर से पर्याप्त तैयारियां नहीं की गयी थीं।

यही नहीं, हमने दुनिया के सबसे ऊँचे पुल पर ट्रेन दौड़ाने का कीर्तिमान तो अपने नाम कर लिया लेकिन जमीन पर बिछी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। आये दिन होते रेल हादसे दर्शा रहे हैं कि संभवत: मंत्रीजी का पूरा ध्यान इस विभाग पर नहीं है। हाल के रेल हादसों में से अधिकांश के पीछे साजिश का एंगल सामने आया है। यदि ऐसा है तो यह भी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी खामी है। यही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के दौरान कुली और प्लेटफॉर्म पर स्टॉल लगाने वाले ही यात्रियों के बचाव में उतरे। एक भी यात्री ने यह नहीं बताया कि रेलवे पुलिस ने किसी की मदद की हो या उसे बचाया हो। साथ ही, भगदड़ की घटना के तत्काल बाद जिस तरह प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गयीं वह दिखाता है कि रेलवे के पास अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था थी। इसलिए सवाल उठता है कि भीड़ को देखते हुए उन स्पेशल ट्रेनों को पहले क्यों नहीं चलाया गया? रेलवे ने गत शनिवार को प्रयागराज के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी लेकिन साधारण ट्रेनों को क्यों नहीं चलाया गया? क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनों से रेलवे को ज्यादा आमदनी होती है और साधारण ट्रेनों को चलाने से ज्यादा लाभ नहीं होता? क्या रेलवे ने अब सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया है?

सवाल और भी कई हैं लेकिन उनके जवाब मिलने की संभावना कम ही है। वैसे यह भी एक तथ्य है कि भारतीय रेलवे भारी दबाव में है। रेलवे में सुधार की अत्यंत जरूरत है। रेलवे को ऐसे मंत्री की भी जरूरत है जिसके पास रेलवे के अलावा अन्य किसी मंत्रालय का कार्यभार नहीं हो ताकि वह रेलवे पर ही पूरी तरह से ध्यान दे पाये। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अश्विनी वैष्णव उच्च शिक्षित, अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन आंकड़े दर्शाते हैं कि उनकी यह योग्यताएं रेलवे के काम नहीं आ पा रही हैं। अश्विनी वैष्णव अक्सर रेलवे की सुनहरी तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं जबकि हकीकत उससे काफी अलग होती है। यही नहीं, आज भले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या देश के अन्य स्टेशनों पर सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा हो लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसी ही व्यवस्था जल्द ही आने वाली होली की छुट्टियों और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी दिखाई देगी?

बहरहाल, देखना होगा कि भारतीय रेलवे का भविष्य कैसा रहता है? वैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिखरे हुए जूते-चप्पलों, टूटी हुई चूड़ियों, कपड़ों, बैंगों के दृश्य और जिन 18 परिवारों में मौत हुई है उनके घर में पसरे मातम का दृश्य हर किसी के मन में सिहरन पैदा कर गये हैं।

डॉलर की चमक में गुम होती पंजाबियत...

पंजाब की हवा, पानी, मिट्टी, संसाधन और खुशनुमा वातावरण वाकई अद्भुत है, लेकिन आज गुरुओं, संतों और महात्माओं की धरती पंजाब के युवा विदेश की ओर एकमुश्त में रुख कर रहे हैं। इससे अधिक इस बात की चिंता है कि इस पलायन के साथ पंजाब की अपनी संस्कृति, विरासत, इतिहास और सिख धर्म पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी सभ्यता को समझना बुराई नहीं है। लेकिन दुष्प्रभाव तब पड़ता है, जब आप इस दीवानगी में अपनी जान जोखिम में डालकर उन देशों में घुसने का गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, और पंजाब में यही हो रहा है।

पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, लेकिन गांवों में अब सिखों की आबादी लगातार कम हो रही है। नकोदर के निकट गांव नवांपिंड के एडवोकेट हरकीकत सिंह का कहना है कि कभी यहां उनके गांव में 700 घर सिख जाटों के होते थे। अब तो चंद घर ही बचे हैं। बाकी सब कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन चले गए हैं। अब तो उनकी अगली पीढ़ी वापस पंजाब आने के लिए तैयार नहीं है। गांव लदड़ के किरपाल सिंह यूके के चाटम कैंट में रहते हैं। उन्होंने दाढ़ी, केश व पगड़ी कुछ नहीं रखा। उनका बेटा जे. सिंह ब्रिटेन में पैदा हुआ, जो सिख विरासत संस्कृति से दूर है। ये महज चंद उदाहरण हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा है और तेजी से बढ़ रही है। यानी पंजाब के पलायन से आने वाली पीढ़ी में सिखिज्म के कमजोर होने का डर भी पनप रहा है।

2008 के बाद पंजाब में एक जबर्दस्त लहर चली, जो लगातार 2023-24 तक चलती चली गई। 2008 में ब्रिटेन ने पंजाब के युवाओं के लिए दरवाजे खोले, तो 2012 के बाद कनाडा ने। हर साल पंजाब से डेढ़ लाख बच्चे कनाडा का रुख करने लगे। अगर वीजा नहीं मिला, तो डंकी रूट अख्तियार कर लिया। हालात यह है कि 2021 से लेकर 2024 तक अमेरिका में जितने शरणार्थी केस फाइल किए गए, उनमें 66 फीसदी पंजाबी थे। 2023 में चार लाख 77 हजार शरणार्थी केस फाइल किए गए। इसमें 66 फीसदी डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। वहीं वैध तरीके से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाने वाले युवा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपने देश से दूर चले जाते हैं। आज पंजाब के 25 लाख लोग विदेश में रह रहे हैं। कनाडा की 3.6 करोड़ की आबादी में पंजाबियों की संख्या 1.3 प्रतिशत है।

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कनाडा में छात्रों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्क वीजा पर विदेश जाना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल पंजाब से 20,000 से अधिक लोग अवैध रूप से पलायन करते हैं। विदेश जाने के लिए एजेंट उनसे मनमाने रुपये वसूलते हैं, जो कि 25 लाख रुपये से लेकर एक-एक करोड़ रुपये तक हो सकते हैं। इन सबका असर यह हो रहा है कि पंजाब के गांव वीरान हो रहे हैं। अंग्रेजी का विस्तार या उसको अपनाना बिल्कुल गलत नहीं है। ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर हमें यह करना ही होगा। हम इसकी कीमत किस तरह से चुकाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा।

पंजाब के नामचीन गायक गिप्पी ग्रेवाल से लेकर जस्सी, बब्बू मान से लेकर गुरदास मान पगड़ी व सिखी वेशभूषा में नहीं दिखते हैं। मनमोहन वारस, कमल हीर, हनी सिंह, शैरी मान आदि बेशक युवाओं के आइकॉन हैं, लेकिन वे पगड़ी नहीं पहनते और उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। तो यह बात उठ रही है कि इन विदेशी चमक-दमक, ग्लैमर और डॉलर की चमक के बीच क्या पंजाबी युवा अपनी संस्कृति व अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट करते समय सिख की पगड़ी उतारी गई। यह निंदनीय है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि जो युवा डंकी रूट से पराए मुल्क में घुस रहे थे और वापस आए हैं, वे कितने सिखी स्वरूप में थे। इस पर मंथन करने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात का ध्यान रखने की है कि कहीं विदेश की चाहत और डॉलर की चमक में हम अपनी पहचान, संस्कृति, विरासत को तो नहीं दांव पर लगा रहे हैं।

लड़ाकू विमान आपूर्ति की कछुआ चाल

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की नैया पार लगाने वाले प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्वतंत्रता और संप्रभुता के प्रति जागरूक अपने देश को एक अनमोल संदेश दिया था, 'जो इतिहास से कुछ नहीं सीखते उनकी नियति होती है इतिहास को दोहराना।' भारत भी अपने सैन्य इतिहास के दो पाठ कभी नहीं भुला सकता। पहला 1962 के चीनी हमले में मिली करारी हार और दूसरा 1971 के भारत पाक युद्ध में अभूतपूर्व विजय का। इन दोनों अवसरों पर देश के शीर्ष नेतृत्व को सशस्त्र सेनाओं से कुछ अप्रिय संदेश मिले थे। चीनी हमले से ढाई वर्ष पहले मार्च 1960 में लेफ्टिनेंट जनरल थोरट ने मैकमोहन लाइन पर संभावित चीनी आक्रमण की चेतावनी देकर कहा था कि भारत में ऐसे आक्रमण का सामना करने की क्षमता नहीं है। वर्ष 1961 में सेना ने ऐसी चेतावनी फिर दी, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे खारिज कर दिया। नतीजा सर्विविदित है।

वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अट्ठानबे हजार सैनिकों का आत्मसमर्पण कराकर एक नया इतिहास रच दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के विरुद्ध फरवरी-मार्च, 1971 में ही युद्ध छेड़ना चाहती थीं, लेकिन तत्कालीन थलसेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने अनोखी ईमानदारी और साहस के साथ प्रधानमंत्री को बताया कि वह इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, और युद्ध लड़ेंगे, तो जीत सुनिश्चित करने के बाद। प्रधानमंत्री ने थलसेनाध्यक्ष की वह सलाह मानी। दिसंबर, 1971 में उस सलाह से मिले सुखद परिणाम को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों सीखों के संदर्भ में वर्तमान वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह ने दोटूक शब्दों में सरकार का ध्यान भारतीय वायुसेना की कमजोर कड़ियों की तरफ आकृष्ट किया है। ये कमजोर कड़ियां हैं लड़ाकू विमानों की चिंतनीय कमी और उसके लिए उत्तरदायी सरकारी क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कछुआ छाप चाल। यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना

1940 में हुई, और 1964 में कंपनी को यह नाम दिया गया।

दरअसल, पिछले दिनों बेंगलुरु में हुए एयरो-इंडिया प्रदर्शनी में एक विमान की टेस्टिंग करते हुए वायुसेनाध्यक्ष को एचएएल के अधिकारियों से यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें सरकारी स्वामित्व वाली इस कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है। समय पर विमानों की डिलीवरी न दे पाने के अपने खराब ट्रैक रिकॉर्ड के कारण उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की खिंचाई की और इसके मिशन मोड में न होने का आरोप लगाया। वायुसेनाध्यक्ष वस्तुत: तेजस एमके 1 ए फाइटर जेट की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित कर पाने में एचएएल की विफलता से नाराज थे। वायुसेनाध्यक्ष की सख्त टिप्पणी के बाद एचएएल प्रबंधन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो तकनीकी समस्याएं थीं, वे दूर कर ली गयी हैं और अब जल्दी ही तेजस विमान की डिलीवरी शुरू हो जाएगी।

गौरतलब है कि एचएएल ने 2025 में भारतीय वायुसेना को 16 एलसीए एमके1 ए जेट विमान देने का वादा किया है, जिसमें 2029 तक कुल 83 जेट होंगे। वायुसेनाध्यक्ष की सख्त टिप्पणी के बाद एचएएल की किसी भी सफाई का बहुत मतलब नहीं है। अनेक विशेषज्ञों ने वायुसेनाध्यक्ष के क्षोभ को जायज बताते हुए यह कहा है कि कई बार विमानों की अकुशलता की कीमत पायलटों को चुकानी पड़ती है। एचएएल की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल उठाते हुए वायुसेनाध्यक्ष ने बताया कि पाकिस्तान और चीन के दोहरे मोर्चों पर युद्ध उस भारतीय वायुसेना के लिए संकटपूर्ण होगा, जिसके पास वांछित 42 स्क्वॉड्रन की जगह केवल 31 लड़ाकू जेट स्क्वॉड्रन हैं। उड़न ताबूत के नाम से कुख्यात पुराने मिग 21 और मिग 23 विमानों का स्थान लेने के लिए जिस आधुनिक सुपरसोनिक हल्के लड़ाकू विमान (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) की परिकल्पना 1980 में की गयी थी, एचएएल ने उसका पहला व्यावहारिक स्वरूप 2011 में प्रस्तुत किया था। लेकिन इसका अंतिम ऑपरेशनल क्लीयरेंस वह 2016 से पहले नहीं दिला पायी। फिर एचएएल ने 2020 तक 40 तेजस विमान वायुसेना को सौंपने और तेजस का परिमार्जित संस्करण तेजस मार्क 1ए के रूप में देने का वादा किया।

वायुसेनाध्यक्ष अमृतप्रीत सिंह ने एचएएल पर घोर सुस्ती और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया है कि पिछले 40 वर्षों में वह पहले 40 तेजस विमान वायुसेना को नहीं दे पायी है और सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सॉफ्टवेयर बदल देने को तेजस मार्क 1ए अर्थात विमान का परिवर्धित-परिमार्जित स्वरूप नहीं कहा जा सकता। एचएएल 'मिशन मोड' में आकर जुझारू ढंग से कर्मचारियों की संख्या और कौशल बढ़ायेगी, तभी तेजस विमान की आपूर्ति कर पायेगी, अन्यथा नहीं।

जहां तक एचएएल की 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली चाल से तेजस विमान की आपूर्ति करने का सवाल है, तो इसके लिए वह अमेरिका से जीइएफ, 404 इंजन की ढीली आपूर्ति को दोष देती है, लेकिन वह यह नहीं बता पाती कि अगर इसरो जैसी संस्था अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की क्षमता बना पायी है, तो तेजस विमान के लिए उपयुक्त इंजन बनाने की क्षमता एचएएल क्यों नहीं विकसित कर पायी। हमारी वायुसेना में आधुनिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के नाम पर दो राफेल लड़ाकू विमान इकाइयों के अतिरिक्त सुखोई मार्क 31 की कुछ स्क्वॉड्रन हैं। शेष सभी पुराने हो चुके सुखोई मार्क 30 और मिराज विमान हैं, और वे भी वांछित संख्या से 25 प्रतिशत की कमी के साथ।

स्पष्टत: अब लड़ाकू विमानों के निर्माण के मामले में एचएएल के एकाधिपत्य को समाप्त करके निजी क्षेत्र को लाने का समय आ गया है। टाटा और एयरबस कंपनियों के सहयोग से अक्तूबर, 2024 में गुजरात में सी-295 फौजी परिवहन विमानों का निर्माण आरंभ हुआ, तो यह घोषणा की गयी कि विदेश में निर्मित 16 विमान आयात करने के बाद सितंबर, 2026 से अगस्त, 2031 के बीच 40 सी 295 विमान गुजरात में बना लिये जायेंगे। उचित यह होगा कि निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां विदेशी सहयोग से लड़ाकू जेट विमानों के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता की नयी मिसाल स्थापित करें और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की खरबों डॉलर के आर्थिक और सैन्य सहयोग की घोषणा का लाभ उठाकर लोहा गर्म रहते हुए ही पांचवीं पीढ़ी के अमेरिकी लड़ाकू जेट एफ 35 के भारत में ही निर्माण करने के बारे में सोचें।

क्या सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर चेतेंगे राजनीतिक दल?

ऋतुपर्ण दवे

गत दीवाली पर घर की रंगाई-पुताई और थोड़ी बहुत मुरम्मत का काम करने वालों को ढूंढते-ढूंढते पसीना आ गया। जो ठौर-ठिकाने हर शहर, कस्बों में लेबर चौक या मजदूर अड्डों के रूप में पहचाने जाते हैं, वे वीरान थे। एक ओर देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है। दूसरी ओर काम के लिए लोग ढूंढे नहीं मिल रहे। अमूमन पूरे देश में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। वजहों के दूरगामी परिणामों को सोचकर ही डर लगता है। क्या हम बहुत जल्द निकम्मों का देश कहलाएंगे? ऐसा भी नहीं कि लोग काम नहीं करना चाहते। जब घर बैठे काफी कुछ मुफ्त मिलेगा तो कोई पसीना क्यों बहाए! रेवड़ी कल्चर की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने लोगों को मुफ्तखोरी का आदी बनाना शुरू कर दिया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया लेकिन तीखी चिंताजनक टिप्पणी ने देश में एक नई बहस शुरू कर दी। आखिर ये है क्या? देश में वोट के बदले मुफ्त बांटने की शुरूआत पहली बार 1967 में हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने एक रुपए में डेढ़ किलो चावल का वायदा किया और इससे कांग्रेस बुरी तरह धराशायी होकर सत्ता से बेदखल हो गई। अकाली दल ने भी पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया। इस तरह शुरू हुआ सिलसिला धीरे-धीरे सभी राज्यों में संक्रमण जैसे फैलता गया। कहीं कम कहीं ज्यादा की होड़ मच गई। अब अमूमन हर चुनावों के दौरान मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज देने की राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा चरम पर है। जहां लोग भी ज्यादा निजी फायदा देख वोट देते हैं वहीं राजनीतिक दलों का मकसद महज चुनाव जीतना होता है। राज्यों, उसकी विकास योजनाओं पर क्या दुष्परिणाम हो रहा सभी बेफिक्र हैं। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुफ्त की योजनाओं को 'लोक कल्याणकारी उपाय' तो बताया लेकिन इनसे जुड़े खर्चों पर जबरदस्त चिंता जाहिर की।

राज्यों के मौजूदा संसाधनों के साथ सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचों और विकास की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। फ्रीबीज की कोई तय परिभाषा नहीं है। पहली बार जुलाई 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अक्तूबर 2024 में आखिरी बार सुनवाई के दौरान केन्द्र को मुफ्त की रेवड़ी परिभाषित करने को कहा गया। यकीनन देश के करदाताओं के पैसों का ऐसा इस्तेमाल हरगिज सही नहीं है। इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 की एक रिपोर्ट 'स्टेट फाइनांस ए रिस्क एनालिसिस' यानी किसी राज्य के वित्त में मौजूद जोखिमों का विश्लेषण पर गहरी चिंता जताई गई। इसमें खास तौर पर पंजाब, बिहार, राजस्थान, केरल और प. बंगाल का जिक्र है जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। मुफ्त योजनाओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है जिसकी शुरूआत दक्षिण से हुई।

पहले मिक्सी, टी.वी., मुफ्त साड़ी,

कंबल, टी.वी., लैपटॉप, साइकिल, बिजली-पानी, गेहूं-चावल का वादा किया जाता था। अब सीधे खातों में पैसे भेजने की गारंटी है जो कई राज्यों में जारी है। 2020 में केंद्र ने मुफ्त राशन योजना शुरू की और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने लगा। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो किसान सम्मान निधि में 4 महीने में 2000 रुपए की सहायता दी जाती है। 2016 से 'उज्ज्वला' योजना में महिलाओं को मुफ्त सिलैंडर तो 2014 से गरीब तबके लिए पी.एम. आवास योजना जारी है। जहां मार्च 2019 तक सभी राज्यों का कर्ज 47.86 लाख रुपए था जो मार्च 2023 तक बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। अभी मुफ्त योजनाओं को अमल में लाने वाले राज्यों की कर्ज की स्थिति देख चिंता होती है।

मध्यप्रदेश में 'लाडली बहना' के चलते 3.8 लाख करोड़, महाराष्ट्र में 'लाड़की बहीणा' योजना की खातिर 7.8 लाख करोड़, कर्नाटक राज्य सरकार की 5 गारंटी खातिर 6.65 लाख करोड़, पंजाब में मुफ्त की बिजली और बस यात्रा हेतु 3.74 लाख करोड़, हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी' योजना की खातिर 3.17 लाख करोड़ तो झारखंड में 'महतारी' योजना खातिर 1.09 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज पहले ही चढ़ चुका है। 2024-25 के बजट में राज्य के वित्तीय घाटे का अनुमान 1.10 लाख करोड़ था जो अब 2 लाख करोड़ के पार जाना संभावित है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल जारी है। मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना' योजना चलाकर भाजपा ने महिलाओं को ऐसा लुभाया कि पहले के मुकाबले प्रचंड बहुमत से जीती। 'लाड़की बहणा' योजना ने महाराष्ट्र में जादू कर भाजपा गठबंधन की शानदार वापसी की। 'मंईया सम्मान' योजना ने झारखंड में जे.एम.एम. गठबंधन को फिर कुर्सी पर बिठाया। यही कर के दिल्ली में भी भाजपा ज्यादा लुभावने तरीकों से मतदाताओं तक पहुंची और 27 बरस बाद शानदार जीत हासिल की।

दुनिया में कई देश अपने सभी नागरिकों को कुछ अहम और लोकोपयोगी सुविधाएं मुफ्त देते हैं। चैक रिपब्लिक, इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस में शिक्षा। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी में बेहद सस्ती उच्च शिक्षा। इंगलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ब्राजील, डेनमार्क में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तो लक्जेमबर्ग और बेल्जियम, स्वीडन के कुछ शहर मुफ्त बस सेवा देकर प्रदूषण कम करने की भूमिका निभा रहे हैं। चीनी दार्शनिक लाओ त्जु ने सच कहा था किसी व्यक्ति को एक मछली देकर उसे एक दिन का भोजन दे देंगे।

लेकिन उसे मछली पकडऩा सिखा देंगे तो जीवन भर भोजन दे सकेंगे। वाकई मुफ्त देने की बजाय लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी जाए। भारतीय परिवेश के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है। लेकिन फ्रीबीज से भारत में परजीवियों का एक वर्ग बनता जा रहा है जो चिंताजनक है। इसे रोकना ही होगा।

बाइक राइडिंग का रखते हैं शौंक तो बेस्ट हैं ये जगहें!

अगर आप भी काम करते-करते थक गए हैं और बाइंकिग का भी शौंक रखते हैं तो और किसी छोटे वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो निकल जाएं इन शानदार सड़कों के सफर पर। जहां ऊंचे पहाड़, गहरे झरने खूबसूरत हरे-भरे जंगल आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि बाइक राइडिंग के शौकीन हैं। यहां पर आप कुदरती नजारों, पहाड़ों, झरनों का भी मजा ले सकते हैं। आइए जानते है उन जगहों के बारे में....

1. लेह, लद्दाख

चारो तरफ पहाड़ों से घिरे इस रूट पर ड्राइविंग का अपना एक अलग ही मजा आता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलता खारदूंगला रोड, जो दुनिया भर में अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है पर घूमने का अलग ही मजा है। इसके अलावा यहां का मैग्नेरटिक रोड खासतौर से मशहूर है। यहां पर टूरिस्ट अप्रैल से अगस्त तक बाइक राइडिंग करने के लिए आते हैं।

2.स्पीति वैली, हिमाचल

लद्दाख से थोड़ी ही दूर हिमाचल की स्पीति वैली है। बाइक से स्पीती वैली तक पहुंचने के लिए काजा, टैबो, स्पीती और पीन वैली जैसी कई खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं। यहां पर सड़कों के किनारे सेब, खूबानी के पेड़ और सतलुज नदी की खूबसूरती के साथ प्राचीन मंदिरों को भी देख सकते है।

3.वालपराई और वाझाचल फॉरेस्ट

बाइक राइडिंग के लिए यह सबसे बेस्ट रूट है। यहां राइडिंग के दौरान घने, हरे-भरे जंगल और कई सारे छोटे-छोटे वाटर फॉल्स का नजारा देखने को मिलता है।।

4.गोवा, मुंबई

इंडिया के बिजनेस कैपिटल मुंबई से गोवा तक बाइक से सफर करना भी काफी मजेदार है। अमेरिका के 101 हाइवे से काफी मिलती-जुलती इस सड़क को इंडिया में बेस्ट कोस्टल राइडिंग के लिए जाना जाता है।

5.वेस्टर्न, अरुणाचल प्रदेश

हिमालय की ऊंची चोटियों को राइडिंग के वक्त देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरिएंस होता है। हालांकि यहां सड़कों की कमी है जिसके चलते ऊंचे-नीचे पहाड़ी रास्तों से गुजरना होता है। सफर के दौरान बर्फ से ढ़की सड़कें, ट्राइबल कल्चर और उनकी अलग सी लाइफस्टाइल को कैमरे में आसानी से कैद किया जा सकता है।

6. जैसलमेर, जयपुर

दोनों तरफ रेगिस्तारन और बीच में हाईवे का सफर में आपको राजस्थानी कल्चर देखने के कई मौके मिलते हैं। इसके साथ ही बीच-बीच में जोधपुर, ओसियां, पोकरन जैसे स्टॉकपेज आते हैं जो आपकी सैर को और भी मजेदार बनाएंगे।

एलीफेंट बीच अंडमान के मशहूर बीचों में से एक है। हैवेलॉक द्वीप पर स्थित इस बीच तक आप नाव से या फिर जंगल ट्रेक करके पहुंच सकते हैं। नीले पानी और चमकदार रेत वाले इस बीच पर आकर आपको बहुद सुकून मिलेगा। यह बीच शानदार कोरल रीफ और स्नॉर्कलिंग के लिए भी जाना जाता है। छुट्टियों में परिवार के साथ यदि आप भीड़भाड़ से अलग शांति और सूकुन वाली जगह की तलाश में है तो अंडमान-निकोबर बेस्ट जगह है। खूबसूरत कुदरती नज़ारों और साफ समुद्री तटों वाले अंडमान की शांति और सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है।

खूबसूरत कुदरती नज़ारों और बीचों की सैर करनी है तो जाएं अंडमान-निकोबार

साफ-सुंदर बीच

पानी से अटखेलियां करना पसंद है तो अंडमान के बीच आपको बुला रहे हैं। यहां के साफ पानी में आप स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, स्कीइंग, पैरास्लाइडिंग, बनान बोट राइड, अंडर वॉटर वॉकिंग आदि एडवेंचर गेम्स का मजा ले सकते हैं। स्कूब डाइविंग के दौरान समुद्र के नीचे रंग-बिरंगी मछलियों से मिलने का अनुभव यादगार बन जाएगा। यहां के बीच अपनी खूबसूरती और स्वच्छता के लिए मशहूर हैं। बीचों की सफेद और चमकीली रेत पर लेटकर जूस और कोल्ड ड्रिंक का मजा लें। क्योंकि अंडमान अपने बीचों के लिए ही मशहूर है तो कुछ खास बीचों की सैर करना न भूलें।

एलीफेंट बीच

यह अंडमान के मशहूर बीचों में से एक है। हैवेलॉक द्वीप पर स्थित इस बीच तक आप नाव से या फिर जंगल ट्रेक करके पहुंच सकते हैं। नीले पानी और चमकदार रेत वाले इस बीच पर आकर आपको बहुद सुकून मिलेगा। यह बीच शानदार कोरल रीफ और स्नॉर्कलिंग के लिए भी जाना जाता है।

राधानगर बीच

हैवलॉक द्वीप पर स्थित यह बीच भी बहुत मनोरम है यहां के दृश्य बेहद सुंदर हैं। अंग्रेजी मैगजीन टाइम द्वारा इसे भारत के सबसे अच्छे बीचों में से एर माना गया और पूरी दुनिया का यह सांतवा बेस्ट बीच है। फोटोशूट के लिए यह बीच एकदम परफेक्ट हैं तो यदि आप अंडमान जाएं तो इस बीच पर फोटो खिंचवाना न भूलें।

विजयनगर बीच

यह बीच भी अंडमान के बेस्ट बीचों में से एक है जो सैलानियों के बीच बहुत पॉप्युलर है। यहां का पानी बहुत साफ है और वातावरण स्वच्छ और सुंदर। यहां आप स्वीमिंगस बोटिंग, सर्फिंग और फोटोग्राफी का मजा ले सकते हैं। अंडमान के बीच फिलहाल अन्य जगहों के बीचों से साफ और सुंदर है, तो आप यदि कुदरत की गोद में सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो अगली छुट्टी अंडमान में बिताएं।

काला पत्थर बीच

यह बीच भी बहुत सुंदर और शांत है। परिवार के साथ सुकून भरे तो पल बिताने वालों के लिए यह परफेक्ट जगह है। यहां की रेत चांदी की तरह चमकती है। इस बीच पर आप सनबाथ का मजा ले सकते हैं।

बेस्ट टाइम

572 छोटे-बड़े द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान। यह देश के सबसे आकर्षक टूरिस्ट प्लेसेज में से एक है। सितंबर से लेकर मार्च तक का समय यहां जाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि तब आप यहां की कुदरती खूबसूरती के साथ ही सुहावने मौसम का पूरा मजा ले सकेंगे।

मलेशिया है बेहद ही खूबसूरत, बिताए गर्मियों की छुट्टियां

मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कदम रखते ही मुझे लगा कि मैं यूरोप, आस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे किसी विकसित देश की धरती पर खड़ी हूं। क्रोम और शीशे से बना यह हवाई अड्डा विश्व के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में एक है। चमकते हुए ग्रेनाइट के फर्श, नवीनतम तकनीक से लैस सभी सुविधाएं तथा डयूटीफ्री सामानों से भरी चमचमाती हुई दुकानें यहां आने वाले हर पर्यटक को सहज ही प्रभावित कर लेती हैं। मुझे लगा कि जब इतने ही दिनों में मलेशिया इतनी तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं? पर इस प्रश्न का जवाब सोचने से पहले ही मुझे पता लगा कि क्वालालम्पुर से पिनांग जाना है और वहां पहुंचने के लिए लगभग 40 मिनट की उड़ान फिर भरनी है। अभी भारतीय समय के अनुसार सुबह के पांच बजे थे, पर हवाई अड्डे की घड़ी सुबह साढ़े सात का समय दिखा रही थी यानी मलेशिया व भारत के समय में ढाई घंटे का अंतर था। मैंने स्थानीय समय के अनुसार अपनी घड़ी मिलाई और पिनांग जाने वाले विमान में बैठ गई।

सुपारी के पेड़ों वाला द्वीप

मलेशिया पर्यटन विभाग की ओर से गए हम आठ लोग थे जिनका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से पिनांग हवाई अड्डे पर टूर गाइड लेना व एडी ने किया। हवाई अड्डे से अपने होटल मुतियारा बीच रिसोर्ट तक जाते हुए लेना व एडी ने हमें पिनांग के बारे में तमाम जानकारियां दीं। पिनांग की खूबसूरती की एक झलक हमें रास्ते में ही मिल गई। हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा पिनांग एक द्वीप है जिसका आकार एक तैरते हुए कछुए की तरह है। पिनांग की खूबसूरती से प्रभावित होकर ही ब्रिटिश रचनाकार सॉमरसेट मॉम ने लिखा था, यदि किसी ने पिनांग नहीं देखा, तो उसने संसार नहीं देखा। मुझे भी यहां आकर लगा कि मॉम ने कुछ गलत नहीं लिखा है। पूर्वी देशों के सबसे सुंदर शहरों में गिना जाता है पिनांग, जिसका नाम इस द्वीप पर बहुतायत से पाए जाने वाले सुपारी के पेड़ों के कारण पड़ा। मलय भाषा में पिनांग पान की सुपारी को कहते हैं। पूरब का मोती कहा जाने वाला यह द्वीप 1786 में सुदूर पूर्वी देशों में ब्रिटिश राज्य का पहला व्यापारिक केंद्र बना, पर आज यह पूरब और पश्चिम के मिलन का एक आकर्षक बिंदु है। चूंकि विश्व के लगभग सभी देशों से पर्यटक यहां वर्ष भर आते रहते हैं, अतः यहां की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्त्रोत पर्यटन है। पर्यटन संबंधी सुविधाएं यहां बहुत विकसित हैं और कई अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का विकास भी काफी अच्छा है।

असर चीनी संस्कृति का

कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के कारण यहां की पुरानी इमारतों में ब्रिटिश स्थापत्य की झलक दिखती है। साथ ही चीनी संस्कृति का प्रभाव आज भी यहां के लोगों पर देखा जाता है। लेना व एडी ने चीनियों द्वारा बनाए गए कुआन यिन तेंग, वाट चैया मांगकालाराम तथा अन्य बौद्ध मंदिरों को दिखाते हुए बताया कि पिनांग की राजधानी जॉज टाउन में चीनियों द्वारा बनाए गए ऐसे कई बौद्ध मंदिर हैं, जहां एक विशेष जाति के चीनी लोग विभिन्न त्योहार मनाने के लिए आज भी इकट्ठे होते हैं। इन मंदिरों पर बनी अत्यंत महीन चीनी पेंटिंग व लकड़ी की नक्काशी से सजे पैनल इस देश के कलाकारों की प्रतिभा का परिचय देते हैं। थाईलैंड की स्थापत्य कला से प्रभावित वाट चैया मांगकालाराम मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटने की मुद्रा में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है।

एक अनुभव अनोखा सा

मीलों तक फैले रेतीले मैदान व नारियल के पेड़ों की कतारों से सजे पिनांग के समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को वर्षों से आकर्षित करते आ रहे हैं। दो दिन की पिनांग यात्रा के दौरान लेना व एडी हमें यहां के लगभग सभी दर्शनीय स्थलों पर ले गए, हमने स्थानीय भोजन का स्वाद लिया और बटरवर्थ तथा पिनांग के द्वीप के बीच चलने वाली फेरी में बैठकर द्वीप के चारों ओर फैले नीले पानी की सैर की। इस फेरी में लगभग 100 से अधिक गाड़ियां लोड की जा सकती हैं और 20-25 मिनट में समुद्र के जरिये अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे आप पिनांग द्वीप तक आ-जा सकते हैं। यह मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। चीन, ब्रिटेन, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों से प्रभावित पिनांग के इतिहास की जानकारी लेते और यहां के शौकीन व बहुत ही मिलनसार लोगों की यादें दिल में लेकर हम पिनांग ब्रिज से होते हुए क्वालालम्पुर की ओर चल दिए। यह ब्रिज पिनांग द्वीप व मलेशिया प्रायद्वीप को जोड़ने वाला विश्व का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज है। यहां इस ब्रिज से जाते हुए पिनांग द्वीप की आखिरी झलक हमें मिल रही थी।

ऐतिहासिक इमारतों के शहर में

क्वालालम्पुर जाते हुए हम मलेशिया के एक और राज्य पेराक से गुजरे जिसका मलय भाषा में अर्थ है चांदी। इस राज्य का यह नाम यहां पाई जाने वाली टिन की खानों के कारण पड़ा जिसका पेराक के इतिहास और अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव रहा। पेराक की राजधानी ईपोह भी साफ सुथरे पार्क, चैड़ी सड़कों व आकर्षक ऐतिहासिक इमारतों के कारण दर्शनीय है। क्वाला कांगसार पेराक का शाही शहर है और यहां की प्राचीन खूबसूरत इमारतों में उबूदिहाह मसजिद व इस्कंदारियाह महल खास हैं। उबूदियाह मसजिद का निर्माण पेराक के 28वें सुलतान इदरीस मुर्शिदुल अदजाम शाह प्रथम के जमाने में शुरू हुआ पर इसके पूरा होने में काफी अड़चनें आई। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान हाथियों द्वारा यहां के इटैलियन मार्बल के फर्शों को तोड़ दिया गया और इसका उद्घाटन 1917 में हो सका। लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना रबर का पेड़ भी क्वाला कांगसार में दर्शनीय है। इसके अलावा पेराक की लाइमस्टोन गुफाएं और उनमें बौद्ध चित्रकला व बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं भी देखने लायक हैं। लेटे हुए भगवान बुद्ध की 24 मीटर लंबी प्रतिमा के दर्शन करने हों, जो मलेशिया में सबसे लंबी प्रतिभा है, तो थाई बौद्ध मंदिर मेकप्रसित जाएं। यह ईपोह से तीन किलोमीटर उत्तर की ओर है। परिवार सहित आने वाले पर्यटकों के लिए आधुनिक राइड व झूलों से लैस बुकिट मेराह थीम पार्क भी यहां है, जो 600 हेक्टेयर में फैले लेक टाउन रिसोर्ट का एक हिस्सा है। पेराक टांग, सैम पोह टांग, शाही मसजिद, जैपनीज गार्डन, दारुल रिदजुआन संग्रहालय, ताम्बुन, सुंगकाई हिरण फार्म, क्वाला वोह जंगल पार्क, लता इस्कंदर वाटर फॉल आदि भी परोक के मुख्य दर्शनीय स्थलों में से हैं।

रोशनी के बाग में

क्वालालम्पुर देखने की उत्सुकता ने हमें चैथे दिन मलेशिया की राजधानी पहुंचा दिया। गार्डन सिटी ऑफ लाइट्स कहे जाने वाले अपने शहर को यहां के लोग प्यार से केएल कहते हैं। 88 मंजिलों वाले विश्व के सबसे ऊंचे फ्री स्टैंडिंग टॉवर्स पेट्रोनाज ट्विन टॉवर्स क्वालालम्पुर में प्रवेश करते ही दिखने लगते हैं। इस्लाम के पांच स्तंभों से प्रेरित यह इमारत मलेशिया की पहचान है। रात को ये टॉवर्स इतने खूबसूरत दिखते हैं कि इनकी ओर से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। क्वालालम्पुर सिटी सेंटर के बीचोंबीच निर्मित पेट्रोनाज टॉवर्स मलय व आधुनिक आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना है। इसके भीतर पेट्रोनाज फिलहारमोनिक हॉल है तथा पेट्रोनाज परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप भी। क्वालालम्पुर में हमने विश्व की चैथी सबसे लंबी (421 मीटर) तथा एशिया की सबसे ऊंची मीनार क्वालालम्पुर भी देखी, जिसके भीतर जाकर ऑब्जर्वेटरी डेक से आप पूरे क्वालालम्पुर तथा क्लैंग वैली का नजारा देख सकते हैं। यहां के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में कई तरह के स्वादिष्ट भोजन का मजा लेते हुए आप क्वालालम्पुर की एक-एक इमारत, पार्क, संग्रहालय व घर आदि दूरबीन से देख सकते हैं। क्वालालम्पुर टॉवर दूरसंचार नेटवर्क, रेडियो व टीवी स्टेशन की ट्रांसमिशन टॉवर भी है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जज के खिलाफ लोकपाल के आदेश पर सुको की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ दिए गए लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल लोकपाल ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या नहीं? जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक की पीठ ने सुनवाई के दौरान लोकपाल के उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई और इसे बेहद परेशान करने वाली बात बताया। पीठ ने उन न्यायाधीश के नाम का खुलासा करने पर भी रोक लगा दी है.

जमीन घोटाले में सिद्धामरैया को बड़ी राहत

नई दिल्ली। बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत के निर्देश के बाद सितंबर 2024 में शुरू की गई लोकायुक्त जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया था। अधिकारियों ने नौकरशाहों, राजनेताओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों, मुदा अधिकारियों और सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती और बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी जैसे प्रमुख लोगों सहित 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की थी। उनके बयानों को वीडियो रिकॉर्ड किया गया और अंतिम रिपोर्ट में दर्ज किया गया। सूत्रों ने बताया कि कुल मिलाकर, विवादित संपत्ति, साइट आवंटन और अधिसूचना प्रक्रियाओं से संबंधित 3,000 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि एमयूडीए मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास किसी भी प्रदेश को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। मान ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल विवादों के निपटारे के लिए गठित 'रावी ब्यास जल अधिकरण' के समक्ष यह बात कही। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनीत सरन, सदस्यों न्यायमूर्ति पी. नवीन राव और न्यायमूर्ति सुमन श्याम तथा रजिस्ट्रार रीता चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और किसी के साथ पानी की एक बूंद भी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

अमित मालवीय ने ट्रंप का वीडियो किया साझा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर भारत की राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो के साथ अमित मालवीय ने कैप्शन में ट्रंप के बयान के अंश साझा किए है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वे (बाइडन सरकार) किसी और को निर्वाचित कराना चाहते थे। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए..यह चैंकाने वाला खुलासा है। ट्रंप ने गुरुवार को मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय चुनाव में अमेरिकी एजेंसी USAID के जरिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा ने भी ट्रंप के बयान को हाथों हाथ लिया और इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप बताया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने हाल ही में अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर? यह पक्के तौर पर भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप की कोशिश है।

दो अलग-अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत

जौनपुर । उत्तर प्रदेश में जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर में गुरुवार सुबह अलग-अलग हादसों में आठ दर्शनार्थियों की मौत हो गई। जबकि हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों का संज्ञान लिया है। झारखंड से दर्शनार्थियों से भरी सूमो महाकुंभ प्रयागराज के बाद अयोध्या जा रही थी। बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर में सूमो को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पांच की मौत ही गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। दूसरा हादसा भी कुछ देर बाद इसी स्थान पर हुआ। दिल्ली के दर्शनार्थियों को लेकर जा रही बस खड़ी राशन लदे ट्रक में जा घुसी।

इसमें चालक और दो महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। एसपी डॉ. कौस्तुभ घायलों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है।

ट्रंप की जेलेंस्की को चेतावनी

युद्ध उनके बिना भी सुलझ सकता है

न्यूयॉर्क । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकाते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध उनके बिना भी खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जेलेंस्की को जल्द से जल्द समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और यह केवल उनका प्रशासन ही कर सकता है। यह बयान उस समय आया जब जेलेंस्की ने शिकायत की कि सऊदी अरब के रियाद में हुई अमेरिकी और रूसी राजनयिकों की बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके देश को बाहर रखकर कोई शांति समझौता किया गया तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद जेलेंस्की ने उन पर हमला करते हुए कहा कि ट्रंप गलत सूचनाओं के जाल में जी रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत पलटवार करते हुए जेलेंस्की को बिना चुनावों के तानाशाह कह दिया। उनका इशारा यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव न कराए जाने की ओर था, जिसे युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले भी ट्रंप विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर ही युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया, जबकि असल में रूस ने 2022 में उस पर हमला किया था। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका यूक्रेन का मुख्य समर्थक है, इसलिए वह जेलेंस्की को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शांति समझौते के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी बीच, रूस और अमेरिका के राजनयिकों की बैठक चार घंटे तक चली, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल थे। दोनों देशों ने बातचीत को सकारात्मक बताया और अपने दूतावासों को पूरी तरह से काम करने देने पर सहमति जताई। ट्रंप ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को यूरोप की तुलना में कहीं ज्यादा आर्थिक बोझ उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 350 बिलियन डॉलर लेने में सफलता हासिल की, जबकि यह एक ऐसा युद्ध था जिसे कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। ट्रंप का कहना है कि यूरोप को भी उतना ही सहयोग देना चाहिए जितना अमेरिका दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका से दूर है जबकि यूरोपीय देशों का पड़ोसी है।

यूपी का बजट- पेश हुआ प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

8.8 लाख करोड़ की हुई घोषणाएं

लखनऊ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है।

योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा

प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश

योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

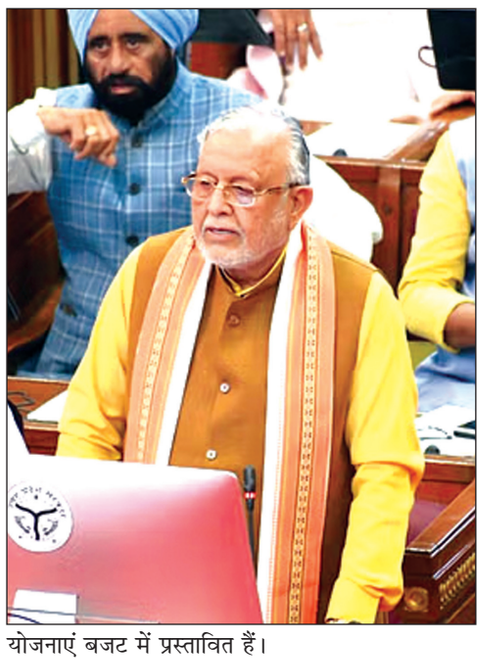

योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

सुरक्षा को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने

स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय% के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रमिकों के लिए नई योजनाएं

वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।

यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

खेल
प्रमुख समाचार

नौ भाषाओं में होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कमेंट्री

मुंबई । जियोस्टार नेटवर्क आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का घर होगा, जो 19 फरवरी से शुरू हो रहे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शानदार प्रस्तुति देगा। दुनिया की शीर्ष आठ टीमें हाई-स्टेक मुकाबलों में भिड़ेंगी, ब्रॉडकास्टर रैखिक टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर एक बेजोड़ देखने का अनुभव प्रदान करेगा। टीवी पर, अंग्रेजी फीड के अलावा, नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 चैनलों पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी कवरेज प्रदान करेगा। डिजिटल पर पहली बार, आईसीसी टूर्नामेंट को 16 फीड पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें नौ भाषाएं शामिल हैं- अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। भाषा विकल्पों के अलावा, जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग को चार मल्टी-कैम फीड द्वारा पूरक किया जाएगा।

सात अलग-अलग देशों के क्रिकेट दिग्गजों की एक स्टार-स्टडेड लाइन-अप दर्शकों के लिए अपनी विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और रोमांचक कमेंट्री लेकर आएगी, जो आईसीसी मेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के उत्साह को बढ़ाएगी। रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, मैथ्यू हेडन, इयान बिशप, वसीम अकरम, रमीज राजा, साइमन डूल, डेल स्टेन, शॉन पोलक और आरोन फिंच अंग्रेजी कवरेज के लिए एक साथ आएंगे, जो मैदान पर होने वाले हाई-ऑक्टेन एक्शन से मेल खाने के लिए मैच विश्लेषण और बेहतरीन कमेंट्री पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हिंदी कवरेज में सुरेश रैना, हरभजन सिंह, वहाब रियाज, वकार यूनिस, संजय मांजरेकर, अंबाती रायुडू, रॉबिन उथप्पा, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, संजय बांगर, आकाश चोपड़ा और दीप दासगुप्ता सहित क्रिकेट के कई दिग्गज शामिल होंगे। इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं की प्रस्तुति में भारतीय क्रिकेट जगत के कई जाने-माने नाम शामिल होंगे, जैसे हनुमा विहारी, अभिनव मुकुंद, एमएसके प्रसाद, आर श्रीधर, मुरली विजय, एस बद्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, सुनील जोशी, केदार जाधव और कई अन्य, जो प्रसारण में अद्वितीय गहराई और विशेषज्ञता लाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

गूगल पे से पेमेंट करने वालों के लिए बुरी खबर!

नई दिल्ली। भारत में अधिकांश लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान कर रहे हैं, जिससे लेनदेन का बड़ा हिस्सा डिजिटल हो गया है। देशभर में हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए का आदान-प्रदान किया जाता है। पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसी कंपनियां यूपीआई पेमेंट सेवाओं में अग्रणी हैं और अब तक ये सेवाएं ज्यादातर मुफ्त रही हैं लेकिन अब शायद लोगों के लिए ये फ्री वाली सेवाएं जल्द ही बंद हो सकती हैं और आपको अलग-अलग सर्विसेज के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप बिल पेमेंट के लिए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो 0.5 फीसदी से 1 फीसदी तक का चार्ज आप लोगों से लिया जाएगा, इस चार्ज के अलावा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। याद दिला दें कि अब तक गूगल पे यूजर्स से बिल पेमेंट्स के लिए कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लेता था।

ईपीएफओ के निवेश नियमों में जल्द ही हो सकता है बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश के तरीके में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से ईपीएफओ के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को 20% से घटाकर 10% करने की मंजूरी मांगेगा। यह बदलाव नवंबर 2024 में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में मंजूर हुआ था। इस कदम के पीछे मुख्य कारण पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में कम रिटर्न और उनकी कम सप्लाई बताई जा रही है। ईपीएफओ द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड के बजाय कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश करने का निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट बॉन्ड आमतौर पर सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को अधिक फायदा हो सकता है। हालांकि, इनमें जोखिम भी अधिक होता है, क्योंकि इन्हें जारी करने वाली कंपनियों के दिवालिया होने की संभावना रहती है।

चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह में डीओसी निर्यात नौ प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। भारत का डी-आयल्ड केक (डीओसी) का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) के दौरान नौ प्रतिशत घटकर 36 लाख टन रह गया है। इस गिरावट का कारण रैपसीड डीओसी और अरंडी डीओसी के निर्यात की खेप का घटना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जनवरी की अवधि के दौरान, कुल डीओसी का निर्यात 36,03,030 टन का हुआ, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 39,74,351 टन था। दस महीने की अवधि में, सोयाबीन डीओसी का समग्र निर्यात एक साल पहले 15.86 लाख टन की तुलना में 17.71 लाख टन तक बढ़ गया। ॅ हालांकि, रैपसीड डीओसी का निर्यात 18,95,454 टन से घटकर 15,42,032 टन रह गया, जबकि अरंडी डीओसी का निर्यात 3,27,261 टन से घटकर 2,58,005 टन रह गया।

कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सावधानी से आगे बढ़े भारत

नई दिल्ली। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बुधवार को कहा कि भारत को कतर के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर, विशेष रूप से पेट्रोरसायन क्षेत्र में सावधानी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दोनों देश इस क्षेत्र में मजबूत हैं। जीटीआरआई ने कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेट्रोरसायन और ऊर्जा संबंधी आयात पर शुल्क रियायतों से घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) में प्रवेश करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 28 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

सबसे तेज बढ़ेगी हमारी जीडीपी; मजबूत घरेलू मांग, निवेश व खपत से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। मजबूत मांग व खपत के दम पर चालू वित्त वर्ष में दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ेगी। अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के बीच सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.3 फीसदी रह सकती है। तीसरी तिमाही में 6.2 से 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है। तीसरी तिमाही के आंकड़े 28 फरवरी को आएंगे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2024-25 में वास्तविक व नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर क्रमश: 6.4 फीसदी व 9.7 फीसदी अनुमानित है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, 36 उच्च आवृत्ति संकेतक अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत दे रहे हैं। स्वस्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिरता को मजबूत कर रही है। तीसरी तिमाही में पूंजीगत खर्च में सुधार दिख रहा है। देशों के बीच तनाव व आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से कैलेंडर वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में मंदी ने भारत सहित अन्य देशों को भी प्रभावित किया। पूंजी निवेश में बेहतर सुधार, आईआईपी वृद्धि दर बढ़कर 4.3 फीसदी, उद्योग की बेहतरी और सेवा क्षेत्र में भारी तेजी, सरकार का नीतिगत हस्तक्षेप।

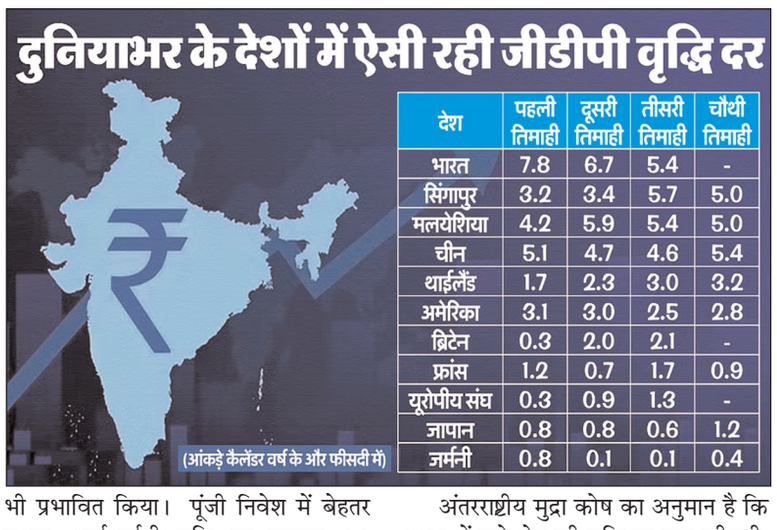

देश	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
भारत	7.8	6.7	5.4	-
सिंगापुर	3.2	3.4	5.7	5.0
मलयेशिया	4.2	5.9	5.4	5.0
चीन	5.1	4.7	4.6	5.4
थाईलैंड	1.7	2.3	3.0	3.2
अमेरिका	3.1	3.0	2.5	2.8
ब्रिटेन	0.3	2.0	2.1	-
फ्रांस	1.2	0.7	1.7	0.9
यूरोपीय संघ	0.3	0.9	1.3	-
जापान	0.8	0.8	0.6	1.2
जर्मनी	0.8	0.1	0.1	0.4

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2025 में यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर एक फीसदी, अमेरिका की 2.7 फीसदी, ब्रिटेन की 1.6 फीसदी और चीन की विकास दर 4.6 फीसदी रह सकती है। भारत की वृद्धि दर 6.5 फीसदी, रूस की 2.2 फीसदी व दक्षिण अफ्रीका की दर 1.5 फीसदी रहेगी। 2024 से 2026 तक भारत की जीडीपी 6.5 फीसदी के स्तर से बढ़ेगी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा, अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ का प्रभाव भारत पर सीमित होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था निर्यात पर कम निर्भरता के साथ घरेलू स्तर पर केंद्रित है। भारत दो वर्षों में 6.7-6.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करेगा। आभूषण, फार्मा, कपड़ा व केमिकल पर ज्यादा टैरिफ लग सकता है। अमेरिका जेनेरिक दवाओं पर अधिक टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे उसके देश में स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाएगी। गोल्डमैन सैश ने कहा, ट्रंप के टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर 0.1 से 0.6 फीसदी के बीच असर पड़ सकता है।

1.80 लाख करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करेगा भारत

नई दिल्ली। मोबाइल फोन निर्यात से चालू वित्त वर्ष में भारत 1.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 40 फीसदी ज्यादा होगा। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक 1.50 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। अकेले जनवरी में 25,000 करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ। 2020-21 में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत के बाद से 6.80 गुना वृद्धि का अनुमान है। पीएलआई योजना के शुरू होने के बाद से भारत में मोबाइल फोन उत्पादन 2,20,000 करोड़ से दोगुना बढ़कर 4,22,000 करोड़ हो गया है। 2024-25 में उत्पादन 5.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है.

नया दुकान एवं स्थापना अधिनियमः आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, राज्य के राजस्व में होगी वृद्धि

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए गए नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम को व्यापारिक जगत और नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों के सुगमतापूर्वक संचालन के साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। खासतौर पर, दुकानों को बिना समय सीमा के संचालित करने की अनुमति मिलने से कारोबारियों के लिए व्यापार सुविधाजनक होगा और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, यह अधिनियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा।

व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को मिलेगी नई गतिः सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत, पंजीयन प्रक्रिया में सरलता, और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (ख्ङ्ग) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि 6 महीने के बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क अनिवार्य होगा।

सातों दिन 24 घंटे दुकान संचालन की स्वतंत्रताः नए अधिनियम के तहत, व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह से व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस पहल से व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पुरानी व्यवस्था के अनुसार, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य न कराया जाए।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकताः सरकार ने व्यापारिक स्वतंत्रता देने के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है। दुकानदारों को श्रम कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों का पूर्ववत पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके तहत साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान अनिवार्य होगा, किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा और श्रम कल्याण योजनाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदमः यह अधिनियम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नए आयाम देने के साथ-साथ व्यापारियों को अधिकतम स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल छत्तीसगढ़ में व्यापारिक गतिशीलता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल व्यापार और उद्योग के लिए एक बड़ा सुधार है, बल्कि एक मजबूत और समावेशी आर्थिक प्रणाली की नींव भी रखता है।

छत्तीसगढ़ में तकनीकी नवाचारों को मिलेगा इसरो का सहयोग

इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौरा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन वी. नारायणन ने भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू-मानचित्रण , प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसरो के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिले और राज्य के विकास को गति मिले।

इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौराः बैठक में बताया गया कि इसरो का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा और राज्य में सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस (त्ङ्कस्) तकनीक और डेटा विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके तहत राज्य में मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, जल स्रोतों का सटीक आकलन, बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ को मिलेगा अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभः इसरो की विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से छत्तीसगढ़ को कृषि, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों मे व्यापक लाभ होगा। कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट डेटा के उपयोग से बेहतर फसल पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार, और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, बाढ़, सूखा और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व-चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना, नगर नियोजन, परिवहन व्यवस्था, और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्याधुनिक स्पेस डेटा के उपयोग सहित वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई की रोकथाम के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसरो और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच साझेदारी से राज्य में तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे युवा वैज्ञानिकों को नवाचारों में योगदान देने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नए युग में इसरो का सहयोग राज्य को भविष्य की तकनीकों से सशक्त बनाएगा, जिससे कृषि, पर्यावरण, जल प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

टेलिकम्यूनिकेशन की आधुनिक तकनीक के माध्यम से शुरू हुई टेली-क्लासेस

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा देने के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया है, जिसमें टेलिकम्यूनिकेशन की आधुनिक तकनीक के माध्यम से टेली-क्लासेस का शुभारंभ किया गया। आज इसके तहत पहला व्याख्यान छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठतम चिकित्सा शिक्षक डॉ. अरविन्द नेरल द्वारा व्याख्यान कक्ष 02 में दिया गया। यह व्याख्यान एच.आई.व्ही./ एड्स से संबंधित था। इसमें डॉ. नेरल ने एड्स रोग की प्रारंभिक जानकारी एच.आई.व्ही. की संरचना और संक्रमण के फैलाव विषय पर विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता, डॉ. विवेक चौधरी ने कहा कि यह महाविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि हमने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस तरह की टेली-क्लासेस से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में लाईव स्ट्रीमिंग के माध्यम से एक साथ व्याख्यान प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इससे उन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को लाभमिलेगा जहां अनुभवी चिकित्सा शिक्षकों की कमी है।राज्य के चिकित्सा शिक्षा में नवाचार का संचार करने के विचार और उद्येश्यों के लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश पर यह सुविधा विकसित की गई है। इसके लिए महाविद्यालय के व्याख्यान कक्ष कं. 02 का ऑनलाईन विडीयो कान्फ्रेसिंग तकनीक के लिये सभी आधुनिक ऑडियो-विजुएल उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। इस कार्य के लिये फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सुमीत त्रिपाठी ने मुख्य रूप से अपनी सक्रियता दिखाई है। उनके तकनीकि मार्गदर्शन में इस सुविधा का वास्तविकता का अमलीजामा पहनाया गया।

इसके लिए रितु कौशिक और ताराचंद पौषार्य के भी उल्लेखनीय सहयोग रहे हैं। इस हेतु डॉ. सुमीत त्रिपाठी, रितु कौशिक और ताराचंद पौषार्य को प्रशस्ति पत्र देकर अधिष्ठाता, डॉ. विवेक चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। लिंक प्रेषित कर इसका जीवंत प्रसारण सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उनके व्याख्यान कक्ष में द्वितीय एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए किया गया। इसमें बिलासपुर, अम्बिकापुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं कोरबा महाविद्यालयों से विद्यार्थियों के अलावा अधिष्ठाताओं व शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए डॉ. अरविंद नेरल ने बताया कि माह मार्च 2025 से ऐसे व्याख्यान नियमित रूप से फाईनल एमबीबीएस पार्ट 02 के विद्यार्थियों के लिये आयोजित किये जायेंगे। इसकी विस्तृत विषयवार समय-सारिणी बना ली गई है, जिसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रेषित किया जायेगा।

लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू

लोरमी । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान संपन्न हुआ. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी अपने गृह ग्राम डिंडौरी में परिवार सहित मतदान करते हुए लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने. लोरमी इलाके में पांच जिला पंचायत सदस्य 25 जनपद सदस्य सहित 147 सरपंचों के लिए आज मतदान हुआ. मतदान के लिए 439 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां पर सुबह 7 से ग्रामीणों मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी. दोपहर 3 बजे मतदान समाप्ति के बाद अब शाम तक मतगणना होना है.मतदान के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पत्रकारों से चर्चा में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर कहा कि दिल्ली में घोटाले की सरकार का अब अंत हुआ है, अब वहां भाजपा के नेतृत्व में आज सरकार का गठन हो रहा है. अब तेजी से विकास का काम होगा.बता दे राज्यमंत्री तोखन साहू डिंडौरी गांव से ही सबसे पहले चोटी इकाई पंच के रूप में चुने गए थे, जिसके बाद विधायक और अब सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं. वही इसको लेकर जिले के अंतिम छोर के गांव यानी अचानकमार टाइगर रिजर्व इलाके में लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

देशभर में लोको पायलटों का विरोध प्रदर्शन

रायपुर. ऑल इण्डिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन के बैनर तले पूरे देश भर में ट्रेन लोको पायलटों ने आज सुबह 7 बजे से भूख हड़ताल शुरू कर दी है. देश भर में करीब 90 हजार लोको पायलटों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर 36 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं.जानकारी देते देते हुए रायपुर रेल मंडल के लोको पायलट रवि कुमार ठाकुर ने बताया कि लोको पायलटों से 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है. काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं. असिस्टेंट लोको पायलट से जबरन हैंड ब्रेक कसवाया जाता है. जो रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. प्रदर्शनकर्ताओं की प्रमुख मांगों में साप्ताहिक विश्राम 16 घंटे करना और साइन ऑन से साइन ऑफ तक 9 घंटे की ड्यूटी लागू करना शामिल है. दो लगातार नाइट ड्यूटी के बाद तुरंत ड्यूटी देने का भी विरोध किया जा रहा है. सातवें वेतनमान में डीए में 50 प्रतिशत वृद्धि पर कर्मियों के टीए में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान था. लेकिन यह बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है. आज सुबह 7 बजे से भूखे पेट रहकर यह हड़ताल कर रहे है. जो लगातार 36 घंटे तक चलेगी.

विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत

रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. 17 अगस्त 2024 से रायपुर जेल में बंद देवेंद्र यादव के समर्थकों में इस फैसले के बाद खुशी की लहर है. उनकी रिहाई शुक्रवार शाम तक हो सकती है. जमानत के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है.पूर्व सीएम ने बताया सत्य की जीत = पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी षड्यंत्र में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है. यह सत्य की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार है.आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि सरकार ने उन्हें गलत तरीके से महीनों जेल में रखा. वहीं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था और देवेंद्र यादव आगे भी जनता के हित में संघर्ष करते रहेंगे.10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में सतनामी समाज के धरना प्रदर्शन के बाद हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं. यह विरोध प्रदर्शन 15-16 मई की रात महकोनी के अमरगुफा में स्थित जैतखाम को तोड़े जाने की घटना के बाद हुआ था. इस प्रदर्शन में देशभर से सतनाम पंथ के अनुयायी शामिल हुए थे।

10 से अधिक स्थानों पर हटाए गए अतिक्रमण

रायपुर । राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह एवं नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।टीम प्रहरी द्वारा आज जी.ई. रोड़ में राजकुमार कॉलेज से साईंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई। इस अभियान में इस अभियान में सतीश ठाकुर, रायपुर नगर पालिक निगम के नगर निवेशक आभाष मिश्रा, जोन 7 जोन कमिश्नर रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नगर निवेश विभाग आशुतोष सिंह, उप अभियंता नगर निवेश विभाग रुचिका मिश्रा नगर निगम के जोन 7 और 5 के सेट्रल टीम, यातायात-पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

मुख्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया तेज

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त के पद को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पद के लिए आए 58 आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए एसीएस स्तर के आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में चार सचिवों की कमेटी गठित की गई है। स्क्रूटनी कमेटी में एसीएस मनोज पिंगुआ के साथ प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव आदिवासी विभाग सोनमणि बोरा और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अविनाश चंपावत शामिल हैं। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप बनाई गई है, जिसमें अंजलि भारद्वाज की याचिका पर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सीआईसी के आवेदनों की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कराई जाए। मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें संकेत मिल रहे हैं कि इसी दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। आमतौर पर राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप ही निर्णय लिया जाता है। इस पद के लिए आवेदन करने वालों में चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन, निवर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा, पूर्व मुख्य सचिव आरपी मंडल, पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, वर्तमान सूचना आयुक्त नरेंद्र शुक्ला, रिटायर आईएएस उमेश अग्रवाल और संजय अलंग, पूर्व सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी समेत 58 उम्मीदवार शामिल हैं।

सीएम साय ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फरवरी) के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान इसकी समृद्ध भाषायी विरासत और बहुभाषी संस्कृति में निहित है। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुख, भतरी सहित अनेक लोकभाषाएँ यहां की सांस्कृतिक आत्मा को संजोए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें अपनी मातृभाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रति जागरूक करता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे समाज की जड़ों से जुड़ने का सेतु भी है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों, लोककथाओं और पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा हमारी मातृभाषाओं में संरक्षित है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा दें, बच्चों को अपनी बोली और भाषा से जोड़ें तथा छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता को संरक्षित करने में योगदान दें।

खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने की भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती पी. टी. उषा ने सौजन्य भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।

बैठक के दौरान श्रीमती पी. टी. उषा ने छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (ड्ढह्र) द्वारा एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दल में विभिन्न खेलों के अनुभवी कोच और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो स्थानीय खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षित करेंगे और उनकी खेल तकनीकों को निखारने में सहायता करेंगे।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रीमती उषा ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल प्रोत्साहन मॉडल के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। राज्य सरकार युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष खेल आयोजनों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 'बस्तर ओलंपिक' का आयोजन किया गया, जिसमें 1.65 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था। उन्होंने बताया कि 2 मार्च 2025 को 'अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक युवा प्रतिभागी भाग लेंगे। इस प्रतिष्ठित मैराथन को तीन श्रेणियों - 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में आयोजित किया जाएगा।

ऑपरेशन साइबर शील्ड- फर्जी सिम बेचने वाले 13 एजेंट गिरफ्तार

रायपुर । साइबर अपराधों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 पीओएस एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच में सामने आया कि इन एजेंटों द्वारा जारी सिम कार्ड संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में इस्तेमाल किए गए थे। अपराध में संलिप्त 7063 सिम कार्ड और 590 मोबाइल की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया जारी है।

जांच और कार्रवाईः पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री अमरेश मिश्रा के निर्देशन में साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना सिविल लाइन रायपुर में अपराध क्रमांक 44/25 के तहत धारा-317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) बीएनएस के तहत जांच की जा रही है।

पहला चरण- 68 म्यूल बैंक अकाउंट धारक/संवर्धक गिरफ्तार।दूसरा चरण- 4 बैंक अधिकारी गिरफ्तार।तीसरा चरण- 13 बैंक खाता संचालकों की गिरफ्तारी, जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। चौथा चरण- अपराध में संलिप्त सिम कार्ड और मोबाइल नंबरों की पहचान के बाद 13 पीओएस एजेंटों की गिरफ्तारी।

गिरफ्तार आरोपी और अपराध का तरीकाः पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नया सिम लेने या पोर्ट कराने वाले ग्राहकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया में डबल थंब स्कैन या आई ब्लिंक कर अतिरिक्त सिम चालू करते थे। जिनके पास आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी होती थी, उनका विवरण वे खुद वेरिफाई कर डी-केवाईसी से फर्जी सिम एक्टिवेट करते थे। ये सिम म्यूल अकाउंट के ब्रोकरों को बेचे जाते थे, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.